कार्यालय भू-सम्पत्ति अधिकारी
श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय
जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)
फॅक्स व फोन नं. 01425-254982

NO.F.13/SKNAU/EO/TENDER/2017-18/ 144/ 5617
दिनांक : 14.06.17

अत्यकालीन ई–निविदा सूचना संख्या 02 (2017-18)

श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के माननीय कुलपति की ओर से उपयुक्त श्रेणी में इस विश्वविद्यालय में पंजीकृत संबंधकक एवं राज्य सरकार/केंद्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेलवे इलयादि में पंजीकृत संबंधकक जोकि राजस्थान सरकार के एच.एच.बी. डी. एवं डी.बी. श्रेणी के संबंधकक के समक्ष हो से निर्माणित कार्यों हेतु ई–टेलफोनिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्रपत्र की जातेगी। निविदा से सम्बंधित विवरण वेब साइट http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in तथा www.sknau.ac.in पर देखा जा सकता है।

<table>
<thead>
<tr>
<th>निविदा के कार्य का नाम</th>
<th>कृषि अनुसंधान उप केन्द्र डिग्री (टोक) में पोड खुदाई का कार्य लागत ₹10.00 लाख</th>
</tr>
</thead>
</table>
| कुल बोली प्रतिभूति (प्रतिशत में) | 1. अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत 
2. इस विश्वविद्यालय में पंजीकृत संबंधक से अनुमानित लागत का 0.50 प्रतिशत |
| निविदा आवेदन/डाउनलोड करने की तारीख | 14 जून 2017 प्रातः 9 बजे से 21 जून 2017 सायं 4 बजे तक |
| निविदा अपलोड करवाने की तारीख | 14 जून 2017 प्रातः 9 बजे से 21 जून 2017 सायं 4 बजे तक |
| तकनीकी निविदा खोजने की तारीख | 22 जून 2017 प्रातः 11 बजे |
| निविदा शुल्क, बोली प्रतिभूति, प्रोसेसिंग शुल्क जमा करवाने की तारीख | 21 जून 2017 सायं 4 बजे तक डी.डी. अथवा बैंकर्स चेक द्वारा |
| यूनिक बिड नंबर | |

भवदीय
(एम.एच.बी. बांगवाल)
भू-सम्पत्ति अधिकारी
No.F.13/SKNAU/EO/TENDER/2017-18/151-505  

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या 02 (2017-18)

श्री कर्न नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के भारतीय कृषि महाद्योग की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में इस विश्वविद्यालय या सांविधानिक निर्माण विभाग में पंजीकृत संबंधित दर्जन के अधिकृत संगठन/ केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठन/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/ डाक एवं दूरसंचार विभाग/रेल इत्यादि में पंजीकृत संबंधित दर्जन के अधिकृत प्रत्यय में ई-प्रोक्युरीमेंट प्रक्रिया हेतु ऑन लाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा कार्यालय ऑनलाइन वेबसाइट से दिनांक 14/06/2017 प्रात: 9 बजे से 21/06/2017 सायं 4 बजे तक हेतु जारी आई ऑनलाइन निविदाएं पुनः: इसी वेबसाइट पर समय कराने की लिंक 21/06/2017 सायं 4.00 बजे तक रहेगी। वेबसाइट पर तकनीकी निविदाएं दिनांक 22/06/2017 को प्रात: 11:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

निविदादाता हाथ निविदा शुल्क, बोली प्रतिभाता तथा प्रोसेसिंग शुल्क इस्टेट ऑफिसर एस.के.एन.एयू जोधपुर के दिनांक 21/06/2017 को सायं 4.00 बजे तक जमा करना आवश्यक है।

प्रोसेसिंग शुल्क प्रत्येक निविदा के लिये 500 रु का होगी। MD,RISL, JAIPUR के नाम देख होगी। निविदा शुल्क एवं बोली प्रतिभाता ही.डी/बेनकर्स चेक द्वारा इस्टेट ऑफिसर एस.के.एन.एयू जोधपुर के नाम देख होगी। इसी विश्वविद्यालय में पंजीकृत संबंधित दर्जन के आधा प्रशंसित बोली प्रतिभाता ही जारी होगी।

इसके संबंधित ज्ञापन को अपने डिजिटल हस्ताक्षर श्री कर्न के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेड करवाना आवश्यक है।

एडशानल फर्मोमेट संकुचित अन बलंकस बड पर मुख्य अभियंता सां.वि. राजस्थान जयपुर के परिपूर्ण श्रेणी: सी.डी.पी.डब्ल्यूडी/ डी.एड.टी.सी/आई.आर.डी-140 दिनांक 20/09/2016 के अनुसार जमा करवानी होगी।

निविदा को निरस्त करने/संशोधन करने/ स्वीकृत करने का पूरा अधिकार अध्यास्ता करकर दिनांक के पास सुरु किया रहेगा।

10 लाख एवं इससे ऊपर के राशि के समस्त टेक्स्ट पर डीकेक्ट लाईब्रिलिटी परियोजना 03 वर्ष है। इसकी गणना कार्य समाप्ति (फाइल) का दिनांक से निविदा प्राप्त अनुसार होगी।
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र सं.</th>
<th>कार्य का नाम</th>
<th>अनुमानित लगाते रूप लाभों में</th>
<th>बोली प्रतिमूलति</th>
<th>निविदा शुल्क</th>
<th>इस वि. वि. में पंजीकृत संवेदन दो से बोली प्रतिमूलति</th>
<th>प्रोसेसिंग शुल्क</th>
<th>कार्य पूर्ण करने की अवधि</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>कृषि अनुसंधान लघु केन्द्र डिग्री (टोक) में RKVY के तहत पूजा को सहायता करने का कार्य</td>
<td>10.00</td>
<td>20,000</td>
<td>1000</td>
<td>5000</td>
<td>500</td>
<td>1 माह</td>
</tr>
</tbody>
</table>

आर.पी.डब्ल्यू.ए. 100 एवं Rajasthan Transparency in public procurement act 2012 & Rules 2013 की शर्त लागू होंगी तथा कार्य के सिक्के लाइब्ररी अवधि कार्य समाप्ति की दिनांक से निविदा प्रप्त्र अनुसार होगा।

नोट :- निविदा से सम्बन्धित पूर्ण विवरण वेब साइट sknau.ac.in, sppp.rajasthan.gov.in, and http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

(एम.एल. चंपावत)

भू - सम्पत्ति अधिकारी

प्रतिलिपि :-
1. श्रीमान मित्र-निवेदक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रस्तुत कर लें कि वे स्वयं या उनका प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित होने का आग्रह करायें।
2. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. सामर्थ्यात्मिक अधिवक्ता / निवेदक कर्मचारीकर्मकारण समायोजन / आधिकारिक इन्जुर्ज
4. श्रीमान निजी संस्थान कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
5. श्रीमान अधीक्षक आँशिकविद्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6. श्रीमान तकनीकी सहायक भू-सम्पत्ति अधिकारी कायमिल जोबनेर।
7. श्रीमान सहायक अभियंता, दुर्गापुर / जोबनेर।
8. लेखापाल / कैदीमण्ड।
9. सम्पर्काधिकार, दुर्गापुर / जोबनेर।
10. इन्जुर्ज लिस्ट, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर। इन निविदा प्रप्त्रो को अविलम्ब राज्य के SPPP पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in तथा विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. नोटिस कार्ड।
12. पर्यटन पत्रकार।
कार्यालय भूमिका सम्पूर्णता अधिकारी
श्री कर्ण नरेंद्र कुमः विश्वविद्यालय
जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)
फेक्स व फोन नं. 01425–254982

(वेबसाइट पर अपलोड करने बाद)

No.F.13/SKNAU/EO/TENDER/2017-18/ 355-525 तिथि : 15.06.17
अल्पकालीन इ-निविदा सूचना संख्या : 02 (2017-18)

श्री कर्ण नरेंद्र कुमः विश्वविद्यालय जोबनेर के माननीय कुलपति महोदय की ओर से विश्वविद्यालय में विभिन्न खातों पर निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त श्रेणी में इस विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकृत संगठनों तथा केन्द्र सरकार व केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों जो कि राज्य सरकार के उपयुक्त श्रेणी के सामग्री तक सभी कार्य का अनुभव रखने वाली फ़र्में से इ-टेंडरिंग के माध्यम से निविदित प्राप्त में ऑन लाइन निविदा प्राप्त की जा रही है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साइट sknau.ac.in, sppp.rajasthan.gov.in व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रं सं.</th>
<th>कार्य का नाम</th>
<th>अनुमानित लागत रूप लाखों में</th>
<th>बोली प्रतिमूलि</th>
<th>निविदा शुल्क</th>
<th>इस दि. दि. में पंजीकृत संबंधको से बोली प्रतिमूलि</th>
<th>प्रोसेसिंग शुल्क</th>
<th>कार्य पूर्ण करने की अवधि</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>कुमः अनुसंधान उप केन्द्र डिप्नी (टांक) में RKVY के तहत पॉड को गहराई करने का कार्य</td>
<td>10.00</td>
<td>20,000</td>
<td>1000</td>
<td>5000</td>
<td>500</td>
<td>1 महूर्त</td>
</tr>
</tbody>
</table>

निविदा प्रप्तो को वेब साइट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संबंद्धक निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेबसाइट व http://eproc.rajasthan.gov.in पर जमा कराएँ।

निविदा हेतु पात्र संबंधको की श्रेणि:—

करसी भी सीमा तक : एए श्रेणी संबंधक
रू. 300 लाख तक : ए श्रेणी संबंधक
रू. 150 लाख तक : वी श्रेणी संबंधक
रू. 50 लाख तक : सी श्रेणी संबंधक
रू. 15 लाख तक : टी श्रेणी संबंधक

1. निविदाता द्वारा बोली प्रतिमूलि अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत एवं निविदा शुल्क भू-सम्पत्ति अधिकारी,श्री कर्ण नरेंद्र कुमः विश्वविद्यालय जोबनेर तथा प्रोसेसिंग शुल्क MD, RISL, Jaipur के नाम दोड़ी / बेकार में भू-सम्पत्ति अधिकारी,श्री कर्ण नरेंद्र कुमः विश्वविद्यालय जोबनेर के कार्यालय में दिनांक 21.06.2017 दोपहर 4:00 बजे तक जमा करवानी है।

2. निविदा प्रप्तो हेतु आवेदन/डाउनलोड की अवधि दिनांक 14.06.2017 प्रातः 9:00 बजे से 21.06.2017, सायं 4:00 बजे तक।
3. (अ) निविदा प्रमाण इलेक्ट्रॉनिक,फॉर्मेट में वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in में दिनांक 14.06.2017 प्रातः 9:00 बजे से 21.06.2017 समय 4:00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं एवं प्राप्त निविदाएं इलेक्ट्रॉनिक,फॉर्मेट में वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर सूचीसम्पूर्ण अधिकारी, श्री कर्म नरेन्द्र कृष्ण विश्वविद्यालय जोधपुर में दिनांक 22.06.2017 को 11:00 बजे खोली जायेगी। यदि किसी कारणबाद उस दिन अवकाश रहता है तो उसके अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएं खोली जायेगी।
(ब) निविदा का समय प्रतियोगी ऑनलाइन होगी।
(स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणबाद यदि शारीरिक निविदाएं नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस में शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।

4. कार्य करने हेतु स्थल उपलब्ध है।
5. कार्यों के कारण हेतु उपरोक्तसुचार सूचीसम्पूर्ण कार्यालय में संबंधक द्वारा दिनांक 14.06.2017 से 21.06.2017 तक किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रमाण को देखा जा सकता है अथवा वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in तथा sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है निविदा प्रमाण में निविदाधारी के लिए योग्यता सूचित तथा निविदाधारी की पात्रता, प्लान,स्थानिक्षेपण; जूनिंग विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का दिवर्ण, नियम, शर्त एवं अन्य विवरण सूचीसम्पूर्ण है।
6. यदि संबंधक का नजदीकी रिस्टोराण (प्रथम रक्त सभ्यता व उनके पति/पत्नी) कार्य से सम्बंधित कार्यालय सूचीसम्पूर्ण अधिकारी एवं श्री कर्म नरेन्द्र कृष्ण विश्वविद्यालय जोधपुर में कार्य रत्न किसी भी तरह पर फर्शपात्र हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबंध रहेगा।
7. विश्वविद्यालय में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त साठाप्तित अधिकारी विश्वविद्यालय अनुमति के बिना संवारितता के 2 वर्ष तक संबंधित अथवा संबंधित कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकते। यदि संबंधक अथवा उसके कर्मचारी में कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विश्वविद्यालय की उक्ति लिखित अनुमति नहीं है तो अनुमंद्र िदिा जा सकेगा।
8. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बदलने निर्देश करने के सामान्य अधिकार सम्मानिक कार्यों के पास सूचीसम्पूर्ण है। आर.पी.डब्ल्यू-100 (आर्थ दिनांक तक संबंधित ) की समस्ति शर्तें नामी होंगी।
9. संबंधक द्वारा उक्त कार्यों के लिए निवारित शासनीय इत्यादि स्वभाविक पास के पास होने या निर्धार ये पर लेने का प्रमाण --पत्र देना होगा।
10. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मान्यता अवधि सम्बंधित है।
11. कार्य के लागत जो अनुसूची में दर्शिये 10.00 लाख से अधिक राशि पर कार्य के दोष निवारण एवं उनके उपर डिकेट लाइब्रेरी परिषद का उत्तर दायित्व पार्श्व पूरा राजस्थान जनस्वास्थ्य के अधीन क्रमांक CE(BLDG) /DLP(BLDG WORK) D-980 दिनांक 12.10.2012 एवं संबंध के लिए क्रमांक जी 624 दिनांक 12.10.2012 लागू होगा।
12. संबंधक द्वारा मिशन हाउस एवं अन्य निविदा के साथ अपलोड करने पर ही उनकी निविदा को खोली जायेगी: --
(क) कार्य का पंजीकरण प्रमाण पत्र
(ख) अनुसूची विवरण कर शासन प्रमाण पत्र जो मिनिंदा जुलाई की शिखर तक बेड हो।
(ग) निविदा में दर्शिये अनुसूची निविदा शॉक, बोली प्रतिमूड्रा एवं प्रोसेसिंग शॉक अपलोड के साथ ही निवारित लिखित एवं रास्ता से पूरा कार्यालय में जमा करायें।
(घ) संलग्न परिणाम के अनुसार 50/- के नाम जुगूड़ियत लड्डू पर घोषणा पत्र।
(ङ) बोली प्रतिमूड्रा में छूट पाने हेतु संबंधित पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्राप्ति।
13. संबंधित को निविदा खुलने से पूर्व किसी भी मूल दस्तावेज को भौतिक रूप से जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। निविदाधारा द्वारा दी गई दरे निविदा खुलने की तिथि से 90 दिनों तक माग रखें।

14. निविदा में सबसे कम दरदाता को क्रम 13 में दशायें गये दस्तावेजों को मूल रूप से प्रस्तुत करने पर ही उसकी निविदा को प्रोसेस कर कार्यालय जारी किये जायेंगे।

15. ई-टेण्डरिंग के लिए निविदाओं हेतु निर्देश:—
   (अ) इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदाधारा निविदा प्रप्तियाँ का इंटरनेट साइट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
   (ब) निविदाधारा में भाग लेने वाले निविदाधारा को इंटरनेट साइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर पंजीकरण करवाना होगा। ऑन लाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सार्टिफिकेट इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में जाने करने हेतु काम आएगा। निविदा दलाल उपरोक्त डिजिटल सार्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत एजेंसी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदाधारा के पास पूर्व में वैध डिजिटल सार्टिफिकेट है नया डिजिटल सार्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
   (ग) निविदाधारा को निविदा प्रप्ति इलेक्ट्रॉनिक फोर्मेट में उपरोक्त में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायेगा कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक काम में स्वीकार नहीं होगा।
   (ड) ऑन लाइन निविदाएं निर्माण दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम संख्या-3 के अनुसार खोली जायेंगी।
   (ब) इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रप्तियों को जमा करने से पूर्व निविदाधारा वह सुनिश्चित कर लेने की निविदा प्रप्तियों से संबंधित तभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रप्तियों के साथ संलग्न कर दी गयी है।
   (र) कोई भी टंडर इलेक्ट्रॉनिकली जमा करने में किसी कारण लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विश्वविद्यालय नहीं होगा।
   (ल) एवं विश्वविद्यालय के अन्य अन्य निविदाधाराओं को सफल निविदाधारा से कार्य पत्र प्राप्त नियम न हो जाने के बाद ही लौटायी जायेंगी। किसी निविदाधारा द्वारा ऑन लाइन टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं लेने पर टेंडर शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क वापिस नहीं लौटाया जाएगा, अन्य शुल्क नियमानुसार वापस कर दिये जायेंगे। कार्य सम्पादन पर देश सभी प्रकार के कर निविदाधारा को बहन करना होगा।

16. निविदाधारा का निविदा की जाति के प्रत्येक पुरुष पर हस्ताक्षर एवं मोहर सहित अपलोड करनी होगी।

[सामान्य उपकरण अधिकारी]
श्री कर्ण नरेन्द्र कुमार विश्वविद्यालय, जोधपुर
परिशिष्ट 'क'
50/- रू. के नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करने वाले घोषणा पत्र का प्रारूप
(नोटेरी से तस्वीर होना चाहिए)

में ....................................................................................................................... (नाम) ........................................ (पिता का नाम) ................ (उम्र) ..

................................................................. जालि .................................................. व्यवसाय ..................................................

नियासी का हैं जो कि शास्त्रयूर्ध्व यह घोषणा करता हूँ कि--

1. मेरी/हामारी फर्म ............................................................................. का एक मात्र मालिक/हिस्सेदार हूँ तथा
मेरे यह घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करने शुरु अधिकृत हैं।

2. मेरी/हामारी फर्म ................. विभाग ........................................ में ..................................

................................................................. श्रेणी मे स्थायी/अस्थायी रूप से पंजीकृत है तथा यह जंपीयन आज दिनांक तक वैध है।

3. मेरे द्वारा भू सम्पति अधिकारी, श्री कर्म नरेन्द्र कृष्ण विष्णुविद्यालय, जोधपुर द्वारा जारी निविदा सूचना
संख्या ......... मे वर्तमान पात्रता सम्बन्धी समस्त सार्वजनिक अवलोकन कर लिया है तथा समस्त सार्वजनिक
मुख्य मान्य है एवं मेरी/हामारी फर्म उक्त निविदा के कार्य क्रम संख्या ......... मे निविदारुए भरने हेतु
पात्र है तथा स्वीकृति के रूप में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं चोट लगाए दी है।

4. इन कार्यों को करने हेतु मेरी/हामारी फर्म के पास आवश्यक समस्त निर्देशसह एवं अन्य संशोधन
उपलब्ध है।

5. मेरे द्वारा उक्त निविदा में प्रस्तुत किए गये समस्त दस्तावेज पूर्णत: वैध है तथा समस्त तथ्य सही
है। मैंने कोई भी तथ्य छिपाया/घटाया/बढ़ाया नहीं है।

उपरोक्त शास्त्र उत्तर के क्रम संख्या 1 से 5 में वर्णित तथ्य मेरी निजी जानकारी अनुसार सही है

जिन्हें मैं सही होना मानता हूँ। ईश्वर उर्मि मदर करें।

फर्म का पूरा पता ................................................................. पैन

................................................................. नंबर

................................................................. मोबाइल नंबर

................................................................. वैक का दिवरण

................................................................. वैक का नाम मध्य शाखा

................................................................. खाता संख्या

................................................................. IFSC Code

(हस्ताक्षर शास्त्र ग्रहिता)

dिनांक .................................................................

स्थान .................................................................
OFFICE OF THE ESTATE OFFICER
SRI KARAN NARENDRA AGRICULTURE UNIVERSITY
JOBNER-303329 Distt. Jaipur (Raj.)

Name of Work:- Digging of existing ponds (under RKVY) at ARSS Diggi Tonk.
Based on:- B.S.R. 2013 P.W.D.(Tonk circle).

<table>
<thead>
<tr>
<th>BSR Item No.</th>
<th>S. No.</th>
<th>Item Description</th>
<th>Quantity</th>
<th>Units</th>
<th>Rate</th>
<th>Total Amount</th>
<th>Total Amount In Words</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.6</td>
<td>1</td>
<td>Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/ manual means over areas (exceeding 30 cm in depth, 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan) including disposal of excavated earth, lead upto 50 m and lift upto 1.5 m, disposed earth to be levelled and neatly dressed: All kinds of soil</td>
<td>2500.00</td>
<td>Cum</td>
<td>113.00</td>
<td>282500.00</td>
<td>INR Two Lakh Eighty Two Thousand Five Hundred Only</td>
</tr>
<tr>
<td>1.7</td>
<td>2</td>
<td>Earth work in excavation/ by mechanical means (Hydraulic Excavator)/ manual means over areas (exceeding 30 cm in depth, 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan) including disposal of excavated earth, lead upto 50 m and lift upto 1.5 m, including stacking of useful material if required and disposed earth to be levelled and neatly dressed: Ordinary Rock</td>
<td>3000.00</td>
<td>Cum</td>
<td>182.00</td>
<td>546000.00</td>
<td>INR Five Lakh Fourty Six Thousand Only</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.26.1</td>
<td>3</td>
<td>Add extra for foundation/trenches/drainage for every additional lift of 1.5 Mtr. or part thereof in All kinds of Soil</td>
<td>2500.00</td>
<td>Cum</td>
<td>22.00</td>
<td>55000.00</td>
<td>INR Fifty Five Thousand</td>
</tr>
<tr>
<td>1.26.2</td>
<td>4</td>
<td>Ordinary or hard rock.</td>
<td>3000.00</td>
<td>Cum</td>
<td>38.00</td>
<td>114000.00</td>
<td>INR One Lakh Fourteen Thousand Only</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Total</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>997500.00</td>
<td>INR Nine Lakh Ninety Seven Thousand Five Hundred Only</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Condition:

1. Extra excavated earth will be disposed of outside the Campus by the contractor at his own cost.

[Signature] ESTATE OFFICER
AGREEMENT NO

Year

OFFICE OF ESTATE OFFICE
SRI KARAN NARENDRA AGRICULTURE UNIVERSITY, JOBNER
Sub-Division

Name of Work
Name of Contractor
Sanction No. ........................................ Dt. .................................. Rs.
Technical Sanction No.
Job No.

(a) Stipulated Date of Start of work
(b) Stipulated Date of Completion of Work
(c) Actual Date of Completion
Extension applied on & Sanctioned

Vide: Estate officer order No. ........................................ Dt. ................................. 201

Details of Documents

(a) Percentage Rate Tender R.P.W.A. 100
(See rule 322 & notes 1 below rule 331)
(b) Schedule A to F
(c) Schedule H
(d) Schedule G
(e) Schedule
(f) General Specification and Conditions of Contract
(g) Contractor's Labour Regulations
(h) 
(i) 

No. ........................................ Date

Copy forwarded to:
1. Comptroller S.K.N.A.U. Jobner,
2. The Accounts Officer/
3. The Assistant Engineer/JEN Shri
4. Auditor
5. Shri/M/s. ........................................ Contractor

Amended Up to 10.03.2010
NOTICE INVITING TENDERS FOR WORKS

1. Tenders are hereby invited on behalf of the Vice Chancellor, Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner, for the work of ............................................................... from enlisted contractors of the appropriate class. Contractors enlisted with CFWD, PWD, Postal, Telecom, Railway, MES, other State Governments/Central Government Undertakings/Organisations equivalent to 'AA' and 'A' Class of Rajasthan are also eligible after giving prescribed Earnest Money to tender for works as under:
   (i) Contractors equivalent to 'AA' Class of Rajasthan Works of which cost exceeds Rs. 1.5 crores
   (ii) Contractors equivalent to 'A' Class of Rajasthan Works of which cost exceeds Rs. 1.5 crores but not exceed Rs. 3.00 crores.

2. Contract document consisting of the detailed plan, complete specifications, the schedule of the quantities of the various classes of work to be done and the set of conditions of contract to be complied with by the person whose tender may be accepted, which will also be found printed in the form of tenders, can be seen at the office of the Estate Officer, SKNAU, Jobner on any working day during office hours.

3. Tenders, which should always be placed in sealed covers with the name of the work written on the envelopes, will be received by the Estate Officer, SKNAU, Jobner up to ...................... am/pm (time) on the ...................... (date) and will be opened by him in his office at ...................... am/pm (time) on ...................... (date) in the presence of such Contractors or their authorized representatives, as are present.

4. Tenders are to be submitted on prescribed forms which can be obtain from the office of the Estate Officer, SKNAU, Jobner, on payment of a sum of Rs. ...................... in cash of by demand draft. The sale of tender forms will start at least...................... days before the date of receipt of tenders. The sale of tender will be closed one day before actual time of receipt of tender. Before submitting tenders, it should be ensured that all the tender papers including Conditions of Contract are signed by the tenderer. Eligibility to get tender forms shall be with reference of the amount mentioned in the NIT.

5. The work is to be completely finished to the satisfaction of the engineer in charge within ...................... months from the 10th day after the date of written order to commence the work.

6. Earnest Money amounting Rs. ...................... must accompany each tender, and each tender is to be in a sealed cover, superscribed "Tender for ......................" and addressed to the Estate Officer, Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner. Earnest Money in bankers cheque in the name of officer inviting tender or Demand Draft of Nationalised/Scheduled Banks, should be deposited with the cashier or authorised clerk and his receipt should be attached with tenders. In case of tenders for works of which tendered cost is Rs. 5 crores and above, Earnest Money of Rs. 10 lac, shall be accepted in cash as above and remaining part of Earnest Money can be accepted either in the form of Bank Guarantee (Form RPWA 87) or in cash. Enlisted contractors shall be required to deposit 1/2% of estimated cost of work as Earnest Money while tendering within their enlistment zone. For outside their zone, 2% Earnest Money shall be required to be deposited.

7. The security deposit @ 10% of the gross amount of the running bill shall be deducted from each running bill and shall be refunded as per rules on completion of the contract as per terms and conditions. However, the amount of security deposit deducted from running bills shall not be converted into any mode of securities like bank guarantee, PFR etc. The earnest money deposited shall however be adjusted while deducting security deposit from first running bill of the contractor. There will be no maximum limit of security deposit. However a contractor may elect to deposit full amount of security deposit in the shape of bank guarantee or any acceptable form of security before or at time of executing agreement. In that case E.M. may be returned only after depositing of full 100% as above. However in case during execution cost of work exceeds as shown at the time of depositing 10% as above, balance security deposit shall be deducted from the Running Account Bills.
8. The acceptance of the tender will rest with the Competent Authority who does not bind it self to accept the lowest tender, and reserves to itself the authority to reject any or all of the tenders received without assigning any reason.

9. Tender forms as issued from the office(s) mentioned above (Para 4), must be returned, with all enclosures, to the Estate Officer, SKAU, on the date of receipt of tenders.

10. No refund of tender fees is claimable for tenders not accepted or forms returned or for tenders not submitted.

11. The tenders for works shall remain open for acceptance for the period as given below from the date of opening of financial bid:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>For tender to be accepted by Estate Officer</th>
<th>45 days</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>For tender to be accepted by Building Committee</td>
<td>60 days</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>For tenders to be accepted by Building Council</td>
<td>90 days</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Note: Communication of acceptance of tender shall also be within the above limits.

If any tenderer withdraws his tender prior to expiry of said validity period or mutually extended period or makes modifications in the rates, terms and conditions of the tender within the said period, which are not acceptable to the department, or fails to commence the work in the specified period, fails to execute the agreement the department shall, without prejudice to any other right or remedy, be at liberty to forfeit the amount of earnest money given in any form absolutely. If any contractor, who having submitted a tender does not execute the agreement or start the work or does not complete the work and work has been put to retendering, he shall stand debarred from participating such retendering in addition to forfeiture of Earnest Money/Security Deposit and other action under agreement.

12. All tenders, in which any of the prescribed conditions are not fulfilled or which have been vitiated by errors in calculations totalling or other discrepancies or which contain over-writing in figures or words or corrections not initialled and dated, will be liable to rejection.

13. Enlisted Contractors, will be required to pay Earnest Money @ 1/2% of estimated cost of work put to tender, in case of work for which they are authorised to tender under Rules for enlistment of contractors, but the amount to the extent of full Earnest money shall be liable to be forfeited in the event of circumstances explained in Clause 11 above. Degree/Diploma holder Engineers may pay Earnest Money equal to one half of the normal rates, subject to the provisions of Rules for enlistment of Contractors.

14. The tender should be accompanied with Income Tax and Sales Tax Clearance Certificates from the concerned departmental authorities, without which the tenders may not be entertained.

15. The whole work, may be split up between two or more contractors or accepted in part and not in entirety if considered expedient.

Signature of the Estate Officer
For end on behalf of the Vice Chancellor SKAU

[Signature]
1. All works proposed for execution by Contract, will be notified in a form of invitation to tender pasted on public places and on a board hung up in the office of and signed by the Estate officer or other duly authorised Engineer. The form of invitation to tender will state the work to be carried out, as well as the date of submitting and opening of tenders and the time allowed for carrying out the work, also the amount of Earnest Money to be deposited with the tender and the amount of the Security Deposit to be deposited by the successful tenderer and the percentage, if any, to be deducted from bills. Copies of the specifications, designs and drawings and estimated rates/scheduled rates and any other documents required in connection with the work signed for the purpose of identification by the Estate officer shall be open for inspection by the Contractor at the office of the Estate officer or other duly authorised Engineer during office hours.

2. In the event of the tender being submitted by a firm, it must be signed separately by each partner, thereof, or in the event of the absence of any partner, it must be signed on his behalf, by a person holding a Power of Attorney, authorising him to do so. Such power of Attorney will be submitted with the tender and it must declare that the firm, is duly registered under the Indian Partnership Act, by submitting the copy of registration certificate.

3. Receipts for payments, made on account of a work when executed, by a firm must also be signed by the several partners, except where the contractor are described in their tender as a firm, in which case the receipts must be signed in the name of the firm by one of the partners or by some other person having authority to give effectual receipts for the firm.

4. Any person, who submits percentage rate tender, shall fill up the usual printed form stating at how much percent above or below the rates specified in Schedule G, he is willing to undertake the work. Only one rate of percentage, more or less, on all the estimated rates/scheduled rates shall be mentioned. Tenders, which propose any alteration in the work, specified in the said form of invitation to tender, or in the time allowed for carrying out the work, or which contain any other conditions of any sort, will be liable to rejection. No single tender shall include more than one work, but Contractors, who wish to tender for two or more works, shall submit a separate tender for each work. Tenders shall have the name and number of work, to which they refer, written outside the envelope.

5. The Estate officer or other duly authorised Engineer will open the tenders in the presence of any contractor(s) or their authorised representatives who may be present at the time, and will announce and enter the rates/amounts of all tenders in the Register of Opening of Tenders, (Form RPWA 20A). In the event of the tender being accepted, a receipt for the Earnest Money deposited shall be given to the contractor, who shall sign copies of the specifications and other documents mentioned in Rule 1. In the event of a tender being rejected, the Earnest Money forwarded with such unaccepted tenders shall, be returned to the Contractor making the same.

6. The Estate officer or any other duly authorised Engineer shall have the right of rejecting all or any of the tender without assigning any reason.

7. The receipt of an Accountant, Cashier or any other official, not authorised to receive such amount, will not be considered as an acknowledgement of payment to the Estate officer or other duly authorised Engineer.

8. The memorandum of work tendered for, memorandum of materials and of tools and plant to be supplied by the Department and their rates, shall be filled in and completed in the office of the Estate officer or duly authorised Engineer before the tender form is issued.

9. If it is found that the tender is not submitted in proper manner, or contains too many corrections and or unreasonable rates or amounts, it would be open for the Estate officer not to consider the tender, forfeit the amount of earnest money and/or delist the contractor.

10. The tenderers shall sign a declaration under the Official Secrets Act for maintaining secrecy of the tender documents, drawings or other records connected with the work given to him in form given below. The unsuccessful tenderers shall return all the drawings given to them.
Declaration:

"We hereby declare that we shall treat the tender documents, drawings and other records, connected with the work, as secret confidential documents, and shall not communicate information derived from the same to any person other than a person to whom we are authorised to communicate the same or use the information in any manner prejudicial to the safety of the same."

11. Any percentage rate tender containing item-wise rates, and any item rate tender containing percentage rate below or above estimated / scheduled rates, will be summarily rejected. However, if a tenderer voluntarily offers a rebate for payment within a stipulated period, this may be considered.

12. On acceptance of the tender, the name of the accredited representative(s) of the contractor (with a photograph and signature attested), who would responsible for taking instructions from the Engineer in charge, shall be communicated to the E.O.

13. Sales tax or any other tax or materials, or Income Tax in respect of the contract shall be governed by Clause 38 A, B, C and D of the Conditions of Contract. Deduction of Income Tax at source will be made as per provisions of the Income Tax Act, in force from time to time.

14. The tender to work shall not be witnessed by a Contractor or contractors who himself/himself has/have tendered or who may and has/have tendered for the same work. Failure to observe the secrecy of the tenders will render tenders of the contractors, tendering as well as witnessing the tender, liable to summary rejection.

15. If on check there are discrepancies the following procedure shall be followed:

(i) Where there is a difference between the rates in figures and words, lower of the two rates shall be taken as valid and correct rate.

(ii) When the rate quoted by the contractor in figures and in words tallies, but the amount is not worked out correctly, the rate quoted by the contractor shall be taken as correct and not the amount worked out.

(iii) While quoting rates, if rate/rates against any item or items are found to be omitted, the rate given in the Schedule 'G' by the department for such items will be taken into account while preparing comparative statement and contractor shall be bound to execute such item on 'G' Schedule rates.

(iv) In case where percentage is given but the ‘above’ or ‘below’ not scored, the tender will be non-responsive.

16. The Contractor shall comply with the provisions of the Apprenticeship Act, 1961, and the rules and orders issued thereunder, form time to time. If he fails to do so, his failure will be a breach of the contract and the original sanctioning authority in his discretion may cancel the contract. The Contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising from an account of violation of him by the provisions of the Act.

17. The Contractor shall read the specifications and study the working drawings carefully before submitting the tender.

18. The site for execution of the work will be made available as soon as the work is awarded. In case, it is not possible for the Department to make the entire site available on the award of the work, the Contractor shall arrange his working programme accordingly. No claim, whatsoever, for not giving the site in full or on award of the work or for giving the site gradually in parts will be tenable. The contractor may satisfy himself regarding site, acquisition of land, approach roads and the like.

19. The tender documents show already the specific terms and conditions on which tenders are required by the University, hence, all tenders should be in strict conformity with the tender documents and should be fulfilled in, wherever necessary, and intimated incomplete tenders are liable to be rejected. The terms and conditions of the tender documents are firm, as such conditional tenders are liable to be rejected.

20. The tenderer, while submitting tender, must provide adequate information regarding his financial, technical and organisational capacity and working experience to execute the work of the nature and magnitude.

21. The Estate officer or other duly authorised Engineer reserves the right to ask for submission of samples as in respect of material for which the tenderer has quoted his rates before the tender can be considered for acceptance. If the tenderer, who is called upon to do so, does not submit within seven days of written order to do so, the E.O. shall be at liberty of forfeiting the said earnest money absolutely.
22. The Contractor shall submit the list of the works, which are in hand (progress), in the following form:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Name of work</th>
<th>Name and Particular of the Sub Division/Division, Where work is being executed</th>
<th>Amount of work</th>
<th>Position of works in progress</th>
<th>Remarks</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

23. The Contractor should quote his rates only in one language i.e. either in Hindi or English. Rates should be quoted in figures, as well as in words. In case a Contractor has quoted rates in both the languages, and the rates so quoted differ, then the lower of the two shall be treated as the rate quoted by the Contractor.

24. All additions, deletions, corrections and overwritings, must be serially numbered and attested by the Contractor at every page, so also by the officer opening the tenders, so as to make further disputes impossible on this score.

25. After acceptance of the tender, the Contractor or all partners (in the case of partnership firm), will append photographs and signatures duly attested, at the time of execution of agreement.

26. If any contractor, who having submitted a tender does not execute the agreement of start the work or does not complete the work and the work has to be put to retendering, he shall stand debarred from participating in such retendering in addition to forfeiture of Earnest Money/Security Deposit and other action under agreements.

27. The tender documents shall be issued to those contractors only having valid enlistment as on the date of issue of documents.

28. (a) If a tenderer reduces the rates voluntarily after opening of the tenders/negotiations, his offer shall stand cancelled automatically, his earnest money shall be forfeited and action for debarring him from business shall be taken as per enlistment rules.

(b) If a non-tenderer offers lower rates after opening of tenders, action for debarring him from business shall be taken as per enlistment rules.

29. Contractors shall submit only unconditional tenders. Conditional tenders are liable to be rejected summarily.
Tender for works

I/We hereby tender for the execution for the Vice Chancellor of the SKJAU of the work specified in the underwritten memorandum within the time specified such memorandum at the rates. (In figures) ------- % (as well as in words) .......................... percent towards the amount, entered in the schedule G in all respects in accordance with the specification, design and drawings and instruction is writing referred in rule 1 in all respect accordance with such conditions as far as applicable. I/We have visited the site of work and are aware of all the difficulties and conditions likely to affect carrying out the work. I/We have fully acquainted myself/myself about the conditions in regard to accessibility of site and quarries/kilns, nature and the extent of ground, working conditions including stacking of materials, installation of tools & plant, conditions effecting accommodation and movement of labour etc. required for the satisfactory execution of contract.

Memorandum

(a) General description of work.................................................................
(b) Estimated cost Rs. .............................................................................
(c) Earnest Money Rs.................................................................. @ 2% for enlisted contractor outside the SKJAU and 1/2% for enlisted in E.O. SKJAU.
(d) Security Deposit:
   (i) “The security deposit @ 10% of the gross amount of the running bill shall be deducted from each running bill and shall be refunded as per rules on completion of the contract as per terms and conditions. However, that amount of security deposit deducted from running bills shall not be converted into any mode of securities like bank guarantee, FDR etc. The earnest money deposited shall however be adjusted while deducting security deposit from first running bill of the contractor. There will be no maximum limit of security deposit.”
   (ii) However, a contractor may elect to deposit of full amount to 10% security deposit in the shape of bank guarantee or any acceptable form of security before or at the time of executing agreement. In that case earnest money may be refunded only after deposit of full 10% as above. However, in case during execution cost of work exceeds as shown at the time of depositing 10% as above, balance security deposit shall be deducted from the Running Account Bills.”
   (iii) Bank Guarantee shall in all cases be payable at the order.
(e) Time allowed for the completion of work (to be reckoned from the 10th day after the date of written order to commence the work) is ................. months. Should this tender be accepted in whole or in part, I/We hereby agree to abide by and fulfill all the terms and provision of the conditions of contract annexed hereto and of the Notice Inviting Tender, or in default thereof, to forfeit and pay the Vice Chancellor SKJAU or his successors in office, the sum of money mentioned in the said conditions. A sum of Rs. .................................................. is for warded hereunder the form of Cash, Bank-draft, Bankers cheque as Earnest Money. This amount of E.M. Shall absolutely be forfeited to the Vice Chancellor SKJAU or his successor in office without prejudice to any other right or remedies the Vice Chancellor of SKJAU or his successor in his office, should I/We fail to commence the work specified in the above memorandum.

Signature of Witness
Witness address & occupation

Date: ..........................................................

The above tender is hereby accepted by me on behalf of the vice chancellor, S.K. NARENDRA Agriculture University, Jhansi.

Date: ..........................................................

Signature of Contractor
Address of Contractor

Estate Officer
CONDITIONS OF CONTRACT

Clause 1: Security Deposit:

The security deposit @ 10% of the gross amount of the running bill shall be deducted from each running bill and shall be refunded as per rules on completion of the contract as per terms, and conditions. However, the amount of security deposit deducted from running bills shall not be converted into any mode of securities like bank guarantee, FDR etc. The earnest money deposited shall however be adjusted while deducting security deposit from first running bill of the contractor. There will be no maximum limit of security deposit.

However, a contractor may elect to deposit full amount of 10% security deposit in the shape of bank guarantee or any acceptable from of security before or at the time of executing agreement. In that case earnest money may be refunded only after depositing of full 10% as above. However, in case during execution cost of work exceeds as shown at the time of depositing 10% as above, balance security deposit shall be deducted from the Running Account Bills.

All compensation or other sums of money payable by the Contractor to University under the terms of his contract may be deducted from or paid by the sale of a sufficient part of his Security Deposit, or from interest arising therefrom, or from any sums, which may be due or may become due to the Contractor by the University on any account whatsoever, and in the event of his Security Deposit being reduced by reason of any such deduction or sale as aforesaid, the Contractor shall within ten days thereof, make good in cash or Bank Guarantee or Nationalised/Scheduled bank, an aforesaid any sum of sums which may have been deducted from or raised by sale of his Security Deposit or any part thereof.

In case of Bank Guarantee of any Nationalised/Scheduled Bank is furnished by the Contractor to the University, as part of the Security Deposit and the bank goes into liquidation or, for any reason, is unable to make payment against the said Bank Guarantee, the loss caused thereby shall fall on the Contractor and the Contractor shall forthwith, on demand, furnish additional security to the University to make good the deficit.

The liability or obligation of the bank under the Guarantee Bond shall not be affected or suspended by any dispute between the Estate officer and the Contractor, and the payment, under the Guarantee Bond by the bank of the university shall not await till disputes are decided. The bank shall pay the amount under the Guarantee, without any demur, merely on a demand from the University stating that the amount claimed is required to meet the recoveries due or likely to be due from the Contractor. The demand, so made, shall be conclusive as regards, to amount due and payable by the bank, under the guarantee limited to the amount specified in the guarantee Bond. The guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the Contractor.

The Bank Guarantee shall remain valid until the specified date unless extended on demand by the Estate officer, which shall include the period of completion of the contract and the defect removal period as per terms of the Agreement. Bank's liability will stand automatically discharged unless a claim in writing lodged with the Bank within the period stated in the Bank Guaranttee including the extended period. After satisfactory completion of the contract and clearance of all dues by the contractor, the Estate officer or duly authorized Engineer will discharge the Bank Guarantee after expiry of the original or the extended period, as the case may be. In case the date of expiry of the Bank Guarantee is a holiday, it will be deemed to expire on the close of the next working day.

University is not concerned with any interest accruing to the Contractor on any form of Security (primary or collateral) lodged by him with the Bank or any; sums payable to sureties obtained by the Bank as counter guarantee to secure its own position. These will be the matters between the Bank and the Contractor.

Clause 2: Compensation for delay:

The time allowed or carrying out the work, as entered in the tender, shall be strictly observed by the Contractor and shall be reckoned from the 10th day after the date of written order to commence the work given to the Contractor. If the contractor does not commence the work within the period specified in the work order, he shall stand liable for the forfeiture of the amount of Earnest Money and Security Deposit. Besides, appropriate action may be taken by the Estate officer to debar him from taking part in future tenders for a specified period or black list him. The walk shall, throughout the stipulated period of completion of the contract, be proceeded with all due diligence, time being essence of the contract, on the part of the contractor. To ensure good progress during the execution of work, the contractor shall be bound, in all cases, in which the time allowed for any work exceeds one month (save for special jobs), to complete 1/8th of the whole of the work before 1/4th of whole time allowed under the contract has elapsed, 3/8th of the work before 1/2 of such time has...
elapsed and 3/4th of the work before 3/4 of such time has elapsed. If the contractor fails to complete the work in accordance with this time schedule in terms of cost in money, and the delay in execution of work is attributable to the contractor, the contractor shall be liable to pay compensation of the University at every time span as below:

A. Time Span of full
   Stipulated period 1/4th 1/2th 3/4th Full
   (………………days) (………………days) (………………days) (………………days)

B. Work to be completed in terms of money
   (Rs………………) (Rs………………) (Rs………………) (Rs………………)

C. Compensation payable by the contractor for delay attributable to the contractor at the stage:
   Scheduled Work remained unexecuted on the last day of (1/4) time span
   Work remained unexecuted on the last day of (1/2) time span
   Work remained unexecuted on the last day of (3/4) time span
   Work remained unexecuted on the last day of contracted full period

Note: In case delayed period over a particular span in stipulated time span is split up and is jointly attributable to university and contractor the competent authority may reduce the compensation in proportion of delay attributable to university over entire delayed over that span after clubbing up the split delays attributable to university and this reduced compensation would be applicable over the entire delayed period without paying any escalation. Following illustration is given first time span of 6 months. Delay is of 30 days which is split over as under:

  5 days (attributable to government) + 5 days (attributable to contractor) + 5 days (attributable to government) + 5 days (attributable to contractor) + 5 days (attributable to government) + 5 days (attributable to contractor). Total delay is thus clubbed to 15 days (attributable to government) and 15 days (attributable to contractor). The normal compensation of 30 days as per clause 2 of agreement is 2.5% which can be reduced as 2.5 15/30 1.25* over 30 days without any escalation by competent authority.

The contractor shall, further, be bound to carry out the work in accordance with the date and quantity entered in the progress statement attached to the tender.

In case the delay in execution of work is attributable to the contractor, the spanwise compensation, as laid down in this clause shall be mandatory. However, in case the slow progress in the one time span is covered up within original stipulated period, then the amount of such compensation levied earlier shall be refunded. The price escalation, if any, admissible under clause 45 of Conditions of Contract would be admissible only on such rates and cost of work, as would be admissible if work would have been carried out in that particular time span. The Engineer-in-charge shall review the progress achieved in every time span, and grant stagewise extension in case of slow progress with compensation, if the delay is attributable to contractor, otherwise with out compensation.

However, if for any special job, a time schedule has been submitted by the Contractor before execution of the agreement, and it is entered in agreement as well as same has been accepted by the Estate officer, the Contractor shall complete the work within the said time schedule. In the event of the Contractor failing to comply with this condition, he shall be liable to pay compensation as prescribed in foregoing paragraph of this clause provided that the entire amount of compensation to be levied under the provisions of this clause shall not exceed 10% of the value of the contract. While granting extension in time attributable to the University reasons shall be recorded for each delay.

Clause 3: Risk & Cost Clause:

The Estate officer the Competent Authority defined under rules may, without prejudice to his rights against the Contractor, in respect of any delay or inferior workmanship or otherwise, or to any claims for damages in respect of any breaches the contract and without prejudice to any rights or remedies under any of the provision of this contract of otherwise, and whether the date for completion has or has not elapsed, by notice in writing, absolutely determine the contract in any of the following cases: -
(i) If contractor having been given by the Estate officer, a notice in writing to rectify, reconstruct or replace any defective work or that the work is being performed in any inefficient or otherwise improper or unworkmanlike manner, shall omit to comply with the requirements of such notice for a period of seven days, thereafter, or if the Contractor shall delay or suspend the execution of the work so that either in the judgment of Estate officer (which shall be final and binding) he will be unable to secure completion of the work by the date for completion of he has already, failed to complete the work by that date.

(ii) If the Contractor, being a company, shall pass a resolution or the Court shall make an order that the company shall be wound up or if a receiver or a manager, on behalf or a creditor, shall be appointed or if circumstances shall arise, which entitle the Court or Creditor to appoint a receiver or a manager or which entitle the Court to make a winding up order.

(iii) If the contractor commits breach of any of the terms and conditions of this contract.

(iv) If the Contractor commits any acts mentioned in Clause 10 hereof:

When the Contractor has made himself liable for action under any of the cases aforesaid, the Estate officer on behalf of the Vice Chancellor of SKNU shall have powers.

To determine or rescind the contract, as aforesaid (of which determination or rescission notice in writing to the Contractor under the hand of the Estate officer shall be conclusive evidence) upon such determination or rescission, the earnest money, full security deposit of the contract shall be liable to be forfeited and shall be absolutely at the disposal of the university.

To employ labour paid by the university and to supply materials to carry out the work or any part of the work, debiting the Contractor with the cost of the labour and the price of the materials (of the amount of which cost and price certified by the Estate officer shall be final and conclusive against the Contractor and crediting him with the value of the work done in all respects in the same manner and at the same rates, as if it had been carried out by the contractor under the terms of this contract. The certificate of the Estate officer, as to the value of the work done, shall be final and conclusive evidence against the Contractor provided always that action under the sub-clause shall only be taken after giving notice in writing to the Contractor. Provided also if the expenses incurred by the department are less than amount payable to the Contractor at his agreement rates, the difference shall not be paid to the Contractor.

(e) After giving notice to the Contractor to measure up the work of the Contractor and to take such part thereof, as shall as unexecuted out of his hands and to give it to another contractor to complete, in which case any expenses which may be incurred in excess of the sum which would have been paid to the original Contractor, if the whole work had been executed by him (if the amount of which excess, the certificate in writing of the Estate officer shall be final and conclusive shall be borne and paid by the original Contractor and may be deducted from any money due to him by university. Under this contract or on any other account, whatsoever, or from his Earnest Money, Security Deposit, Enlistment Security or the proceeds of sale thereof, or a sufficient part thereof as the case may be. In the event of any one or more of the above courses being adopted by the Estate officer, the Contractor shall have no claim to compensation for any loss sustained by him by reason of his having purchased or procured any materials or entered into any engagements or made any advances on account or with a view to the execution of the work or the performance of contract. And, in case action is taken under any of provisions aforesaid, the Contractor shall not be entitled to recover or be paid, any sum for any work thereof or actually performed under this contract unless and until the Estate officer has certified, in writing, the performance of such work and the value payable in respect thereof, and he shall be only entitled to be paid the value so certified.

Clause 4: Contractor remains liable to pay compensation, if action not taken under Clause: 3

(i) In any case in which any of the powers conferred by Clause 3 hereof, shall have become exercisable and the same shall have not been exercised, the non-exercise thereof shall not constitute waiver of any of the conditions hereof, and such power shall, not with standing, be exercisable in the event of any future case of default by the Contractor for which, by any clause or clauses hereof, he is declared liable to pay compensation amounts to the, whole of his Security Deposit/Earnest Money/Enlistment Security and the liability of the Contractor for past and future compensation shall remain unaffected.
Power to take possession of, or require removal, sale of Contractor's Plant:

(ii) In the event of the Estate officer putting in force, powers vested in him under the proceeding, clause 3 he may, if he so desires, take possession of all or any tools, plants, materials and stores, in or upon the works or the site, thereof, or belonging to the contractor or procured by him and intended to be used for the execution of the work or any part thereof, paying or allowing for the same in account, at the contract rate, or in case of these not being applicable, at current market rates, to be certified by the Estate officer or duly authorized Engineer (whose certificate, thereof, shall be final and conclusive), otherwise require him to remove such tools, plant, materials or stores from the premises (within a time to be specified in such notice), and in the event of the Contractor failing to comply with any requisition, the Estate officer or duly authorized Engineer may remove them at the Contractor's expenses sell them by auction or private sale on account of the Contractor and at his risk in all respects, and the certificate of the Estate officer or duly authorized Engineer, as to the expenses of any such removal, and the amount of the proceeds and expenses of any such sale shall be final and conclusive against the Contractor.

Clause 5: Extension of Time:

If the Contractor shall desire an extension of time for completion of the work on the ground of his having been unavoidably hindered in its execution or on any other grounds, he shall apply, in writing, to the Estate officer within 30 days of the date of the hindrance, on account of which he desires such extension as aforesaid, and the Authority Competent to grant extension under the rules/directions of powers or other duly authorized Engineer shall, if in his opinion, (which shall be final) reasonable grounds be shown therefor, authorize such extension of time, if any, as may, in his opinion, be necessary or proper, if the period of completion of contract expires before the expiry of the period of one month provided in this Clause, the application for extension shall be made before the expiry of the period stipulated for completion of the contract. The competent authority shall grant such extension at each such occasion within a period of 30 days of receipt of application from contractor and shall not wait for finality of work. Such extensions shall be granted in accordance with provisions under clause (2) of this agreement.

Clause 5 A: Monthly Return of Extra Claims:

Contractor has to submit a return every month for any work claimed as extra. The Contractor shall deliver the return in the office of the Estate officer and obtain Receipt Number of the Receipt Register of the day on or before 10th day of every month during the continuance of the work covered by this contract, a return showing details of any work claimed as extra by the contractor which value shall be based upon the rates and prices mentioned in the contract or in the Schedule of Rates in force in the District at the time being. The contractor shall be deemed to have waived all claims, not included in such return, and will have no right to enforce any such claims not included, whatsoever be the circumstances.

Clause 6: Final Certificate:

On completion of the work, the Contractor shall send a registered notice of the Estate officer giving the date of completion and sending a copy of it to the officer accepting the contract, on behalf of the Vice chancellor and shall request the Estate officer to give him a certificate of completion, but no such certificate shall be given nor shall the work be considered to be complete until the contractor shall have removed from the site on which the work shall be executed, all scaffolding, surplus materials and rubbish and cleared off the dirt from all wood work, doors, walls, floors, or here parts of any building, on or about which the work is to be executed or of which he may have possession for the execution thereof, he had filled up the pits. If the contractor shall fail to comply with the requirements of this Clause as to removal of scaffolding, surplus materials and rubbish and cleaning off dirt and filling of pits on or before the date fixed for completion of the work, the Engineer-in-charge may, at the expense of the contractor remove such scaffolding, surplus materials and the rubbish and dispose of the same, as he thinks fit, and clean off such dirt and fill the pits as aforesaid, and the contractor shall forthwith pay the amount of all expenses, so incurred, and shall have no claim in respect of any such
scaffolding or surplus materials, as aforesaid, except for any such actually realized by the sale thereof. On completion, the work shall be measured by the Estate officer himself or through his subordinates, whose measurements shall be binding and conclusive against the contractor. Provided that, if subsequent to the taking of measurements by the subordinate as aforesaid, the Estate officer had reason to believe that the measurements taken by his subordinates and acknowledged by the Contractor and to take measurements again, after giving reasonable notice to the Contractor, and such re-measurements shall be binding on the Contractor.

Within ten/thirty days of the receipt of the notice, Estate officer shall inspect the work and if there is no visible defects on the face of the work, shall give the contractor a certificate. If the engineer incharge find that the work has been fully completed it shall be mentioned in the certificate so granted. If, on the other hand, it is found that there are certain visible defects to be removed, the certificate to be granted by Estate officer shall specifically mention the details of the visible defects along with the estimates of the cost for removing those defects. The final certificates of the work shall be given after the the visible defects pointed out as above have been removed.

(Delete whichever is not applicable). (Ten days will apply to works at the headquarters of Estate officer and thirty days for works at other place.)

Clause 7: Payment on Intermediate Certificate to be regarded as advance:

No payments shall be made for works estimated to cost less than rupees twenty five thousand, till after the whole of the works shall have been completed and a certificate of completion given. But in the case of works estimated to cost more than Rupees twenty five thousand, the contractor shall on submitting the bill therewith, be entitled to receive a monthly payment proportionate of the part, thereon, then approved and passed by the Estate officer whose certificate of such approval and passing of sum, so payable, shall be final and conclusive. Running Account Bill shall be paid within 15 days from presentation. But all such intermediate payments shall be regarded as payments by way of advance against the final payment only and not as payments for work actually done and completed, and shall not prejudice the requiring of bad and imperfect or unskilful work to be removed and taken away and re-constructed or re-erected, or considered as an admission of the due performance of the contract, or any part thereof, in any respect, or the accruing of any claim, nor shall it conclude, determine, or effect in any way the powers of the Estate officer under these conditions or any of them to the final settlement and adjustment of the accounts of otherwise in any other way very of the effect the contract. The final bill shall be made/submitted by the Contractor within one month of the date fixed or completion of the work otherwise the Estate officer certificate of the measurements and of the total amount payable for the work accordingly shall be final and binding on all parties.

Clause 7 A: Time Limit for Payment of Final Bills:

The final bill shall be paid within 3 months on presentation by the contractor after issuance of final completion certificate in accordance with clause 6 of the conditions of contract. If there shall be any dispute about any items of the work, then the undisputed item(s) only, shall be paid within the said period of 3 months. If a final bill (which contains no disputed item or disputed amount of any item) is not paid within the period of 3 months from presentation of final bill or 6 months from the date of receipt of registered notice regarding completion of work in accordance with clause 6 of the condition of the contractor the defect(s), if any shall be brought to the notice of the higher authority. The period of 3 months shall commence from the date of rectification of the defects. The higher authority shall ensure that no case final bill should be left unpaid after 6 months from the receipt of, registered notice regarding completion of work. The contractor shall submit a memorandum of the disputed items along with justification in support within 60 days from the disallowance thereof, and if he fails to do so, his claim shall be deemed to have been fully waived and absolutely extinguished.

Clause 8: Bills to be submitted monthly:

A bill shall be submitted by the Contractor each month or on before the date fixed by Estate officer for all work executed in the previous month and the Estate officer shall take or cause to be taken the requisite measurement for the purpose of having the same verified and the claim, as far as admissible, authorized or paid. If possible, before the expertly
of ten days from the presentation of the bill. If the contractor does not submit the bill within the time fixed, as aforesaid the Estate officer may deputize a subordinate to measure up the said work in the presence of the Contractor, whose signature in the Measurement Book will be sufficient warrant and the Estate officer prepare a bill from such Measurement Book, which shall be binding on the Contractor in all respects.

Clause 8 A: Contractor to be given time to file objection to the Measurements, recorded by the Department:

Before taking any measurement of any work, as have been referred to in preceding Clauses 6, 7 & 8 the Estate officer or subordinate, deputized by him shall give reasonable notice to the contractor. If the contractor fails to appear at the time of taking measurements after such notice or fails to sign or to record the difference within a week from the date of measurement in the manner required by the Estate officer, then in any such event, the measurements taken by the Estate officer or by the subordinates deputized by him, as the case may be, shall be final and binding on the Contractor and the Contractor shall have no right to dispute the same.

Clause 9: Bill to be on printed forms:

The Contractor shall submit all bills on the printed forms, to be had on application, at the office of the Estate officer and the charges in the bills shall always be entered at the rates specified in the tender or in the case of any extra work ordered in pursuance of these conditions, and not mentioned or provided for in the tender at the rates herein after provided for such work.

Clause 9 A: Payment of Contractor's Bills to Banks:

Payments due to the Contractor may if so desired by him, be made to his Bank instead of direct to him, provided that the contractor has furnished to the Estate officer (i) an authorization in the form of a legally valid document (such as a Power of Attorney conferring authority on the Bank to receive payments, and (ii) his own acceptance of the correctness of the account made out, as being due, to him, by University or his signature on the bill or other claim preferred against University before settlement by the Estate officer of the account of claim, by payment to the Bank. While the receipt given by such bank shall constitute a full and sufficient discharge for the payment, the Contractor should, whenever possible, present his bill duly receipted and discharged through his banker. Nothing, herein contained, shall operate to create in favour of the Bank any rights vis-a-vis the Vice Chancellor.

Clause 10: Stores supplied by Government:

If the specification or estimate of the work provides for the use of any special description of material, to be supplied from Estate officer stores, or if, it is required that contractor shall use certain stores to be provided by the Estate officer specified in the schedule or memorandum hereto annexed, the Contractor shall be bound to procure and shall be supplied such materials and stores as are, from time to time, required to the used by him for the purpose of the contract only, and the value of the full quantity of materials and stores, so supplied, at the rates specified in the said schedule or memorandum, any be set off or which may be deducted from any sum, then due or thereafter become due, to the contractor under the contract or otherwise against or from the Performance Guarantee and or Security Deposit or the proceeds or sale, if the same is held in University securities, the same on a sufficient portion thereof being in this case, sold for this purpose. All material supplied to the contractor, either from departmental store or with the assistance of the university shall remain the absolute property of University. The Contractor shall be the trustees of the Stores/Materials, so supplied/procured, and these shall not, on any account be removed from the site of work and shall be, all times, open to inspection by the Estate officer. Any such material, unused and in perfectly good condition at the time of completion or determination to pay the price of such materials in accordance with the provision of Clause 10 B. But the Contractor shall not be entitled to return any such materials, unless with such consent, and shall have no claim for compensation on account of any such materials, so supplied to him as aforesaid being unused by him, or for any wasteage or damage to any such materials. For the stores returned by the contractors, he shall be paid for at the price originally excluding storage charges, in case of materials supplied from departmental stores and actual cost including freight, cartage, taxes etc., paid by the Contractor.
in case of supplies received with the assistance of University which, however, should in no case exceed market rate prevailing at the time the materials are taken back. The decision of the Estate officer, as to the price of the stores returned, keeping in view it conditions etc., shall be final and conclusive. In the event of breach of the aforesaid condition, the Contractor shall in addition to throwing himself open to account for contravention of the terms of the license or permit and/or for criminal breach of trust, pay to the university all advantages or profits resulting, or which in the usual course, would result to him by reason of such breach. Provided that the Contractor shall, in no case be entitled to any compensation or damage on account of any delay in supply or non-supply or non-supply thereof, all or any such materials and stores.

Clause 10 A: Rejection of materials procured by the Contractor:

The Estate officer shall have full powers to require the removal from the premises of all materials which in his opinion, are not in accordance with the specifications and, in case of default, the Estate officer shall be liberty to employ other person (s) to remove the same without being answerable or accountable for any loss of damage, that may happen or arise to such materials to be substituted thereof, and in case of default, Estate officer may cause the same to be supplied and all costs, which may attend such removal and substitution, are to be born by the Contractor.

Clause 10 B: Penalty in case of excess consumption:

The Contractor shall also be charged for the materials consumed in excess of the requirements calculated on the basis of standard consumption approved by the department, at double the issue rate including storage and supervision charges or market rate, which ever is higher. A Material Supply and Consumption Statement, in prescribed Form RPWA 36A shall be submitted with every Running Account Bill, distinguishing material supplied by the University and material procured by the Contractor himself. The recovery for such material shall be made from Running Account Bill next after the consumption and shall not be deferred Certificate of such nature shall be given in each Running Account Bill.

Clause 10 C: Hire of Plant and Machinery:

Special Plant and Machinery, required for execution of the work, may be issued to the Contractor, if available, on the rates hire charges and other terms and conditions as per departmental rules, as per Schedule annexed to these conditions. Rates of such plant & Machinery shall be got revised periodically so as to bring them up pari with market rate.

Clause 11: Works to be executed in accordance with specifications, Drawings Order etc.:

The Contractor shall execute the whole and every part of the work in the most substantial and satisfactory manner and both as regards materials and otherwise in every respect in strict accordance with the Specification. The Contractor shall also confirm exactly fully and faithfully to the designs, drawings and instructions in writing relative to the work signed by the Estate officer and lodged in his office and to which the Contractor shall entitled to have access at such office or on the site of the work for the purpose of the inspection during office hours and the contractor shall, if he so required, be entitled at his own expense, to make or cause to be made copies of specifications and of all such designs, drawings and instructions, as aforesaid. A certificate of executing works as per approved design and specifications etc. shall be given on each Running Account Bill.

The specifications of work, material, methodology of execution, drawings and designs shall be signed by the Contractor and Estate officer while executing agreement and shall form part of agreement.

Clause 12:

The Estate officer shall have power to make any alterations, omissions or additions to or substitutions for the original specifications, drawings, designs and instructions that may appear to him to be necessary during the progress of the work and the contractor shall carry out the work in accordance with any instructions which may be given to him in writing signed by the Estate officer, and such alteration, omission, additions or substitutions shall not invalidate the contract and any altered, additional or substituted work, which the contractor may be directed to do in the manner above.
specified as part of the work, shall be carried out by the contractor on the same conditions in all respects on which he agreed to do his main work. The time for the completion of the work shall be extended in the proportion that the altered or substituted work bears to the original contract work, and the certificate of the Estate officer shall be conclusive as to such proportion. The rates for such additional altered or substituted work under this clause shall be worked out in accordance with the following provisions in their respective order.

(i) If the rates for the additional, altered or substituted work are specified in the contract for the work, the contractor is bound to carry out the additional, altered or substituted work at the same rates as per specified in the contract for the work.

(ii) If the rates for the additional, altered or substituted work are not specifically provided in the contract for the work, the such rates will be derived from the rates for a similar class of work as are specified in the contract for the work.

(iii) If the rates for the altered, additional or substituted work cannot be determined in the manner specified in the sub-clauses (i) to (ii) above, then the rates for such composite work item shall be worked out on the basis of the concerned Schedule of Rates of the District/area specified above minus/plus the percentage which the total tendered amount bears to the estimated cost of the entire work put to tender. Provided always that if the rate for a particular part or parts of the item is not in the Schedule of Rates, the rate for such part of parts will be determined by the Estate officer on the basis of the prevailing market rates when the work was done.

(iv) If the rates for the altered, additional or substituted work item cannot be determined in the manner specified in sub-clauses (i) to (ii) above, then the contractor shall within 7 days of the date of receipt of order to carry out the work, inform the Estate officer of the rate which it is his intention to charge for such class of work supported by analysis of the rate or rates claimed and the Estate officer shall determine the rates on the basis of prevailing market rates, and pay the contractor accordingly. However, if the Estate officer by notice in writing, will be at liberty to cancel his order to carry out such class of work and arrange to carry it out in such manner as he may consider advisable. But under no circumstances, the contractor shall suspend the work on the plea of non-settlement of rates on items falling under the clause.

(v) Except in case of item relating to foundations contained in sub-clause (i) to (v) above shall not apply contract or substituted items as individually exceed the percentage set out in the tender documents under Clause 12A.

For the purpose of operating of Clause 12(v) the following works shall be treated as work relating to foundations:

(a) For buildings, compound wall, plinth level or 1.2 meters (4 ft) above ground level whichever is lower, excluding items above flooring and D.P.C. but including base concrete below the floors.

(b) For abutments, piers, retaining wall of culverts and bridges, walls of water reservoir and the bed of floor level.

(c) For retaining walls, where floor levels in not determinate 1.2 meters above the average ground level or bed level.

(d) For roads, all items of excavation and filling including treatment of sub base and subsoil work.

(e) For water supply lines, sewer lines underground storm water drains and similar work, all items of work below ground level except items of pipe work for proper masonry work.

(f) For open storm water drains, all items of work except lining of drains.

(g) Any other items of similar nature which Estate officer may decide relating to foundation.

The rate of any such work, except the item relating to foundations, which is in excess of the deviation limit shall be determined in accordance with the provisions contained in Clause 12A.

Clause 12A:

The quantum of additional work for each item shall not exceed 50% of the original quantity given in the agreement and the total value of additional work shall not exceed 20% of the total contract value, unless otherwise mutually agreed by the E.O. and the Contractor. This limit shall not be applicable on items relating to foundation work which shall be executed as per original rates or provision of clause 12(i) to (iv).
In case of contract substituted items or additional items, which results in exceeding the deviation limit laid down in this clause except items relating to foundation work which the contractor is required to do under clause 12 above, the contractor shall within seven days from the receipt of order, claim revision of the rate supported by proper analysis in respect of such item for quantities in excess of the deviation limit notwithstanding the fact that the rates for such items exist in the tender for the main work or can be derived in accordance with provision of sub clause (ii) of clause 12 and the Estate officer may revise their rates having diverted in accordance with the provision of sub clause may revised there rates having regard to the prevailing market rates and the contractor shall be paid in accordance with the rates so fixed. The Estate officer shall, however, be at liberty to cancel his order to carry out such increased quantities of work by giving notice in writing to the contractor and arrange to carrying it out in such manner on he may consider advisable. But under no circumstances, the contractor shall suspend the work on the plea of non-settlement of rates of items falling under this Clause.

All the provision of the preceding paragraph shall equally apply to the decrease in rates of items for quantities in excess of the deviation limit notwithstanding the fact that the rates for such items exist in the tender for the main work or can be derived in accordance with the provision of sub-clause (ii) of the preceding clause 12 and E.O. may revise such rates having regard to the prevailing market rates unless otherwise mutually agreed by E.O. and the Contractor.

Clause 13: No compensation for alterations in or restriction of work to be carried out:

If, at any time after the commencement of the work, the University shall, for any reason, whatsoever, not require the whole work thereof, as specified in the tender, to be carried out, the engineer-in-charge shall give notice in writing, if the fact to the Contractor, who shall have no claim to any payments or compensation, whatsoever an account of any profit or advantage, which he might have derived from the execution of the work in full but which he did not derive in consequence of the full amount of the work not having been carried out. Neither, shall he have any claim for compensation by reason of alterations having been made in the original specifications, drawings and design and instructions, which shall involve any curtailment of the work as originally contemplated. Provided, that the Contractor shall be paid the charges for the cartage only, of materials actually brought to the site of the work by him for bona fide use and rendered surplus as a result of the abandonment or curtailment of the work or any portion thereof, and taken them back by the Contractor provided, however that the engineer-in-charge shall have, in all such cases, the option of taking overall or any such materials at their purchase price or at local market rates whichever may be less, in the case of such stores, having been issued from University Stores, charges recovered, including storage charges, shall be refunded after taking into consideration any deduction for claim on account of any deterioration or damage while in the custody of the contractor, and in this respect the decision of the E.O. shall be final.

Clause 14: Action and compensation payable in case of bad work:

If, it shall appear to the Building Council or any authorized or the Estate officer or his subordinates in-charge of the work, or to the committee of retired officers/officers appointed by the University for the purpose that any work has been executed with unsound, imperfect or unskilful workmanship, or with material of any inferior description, or that any material or articles provided by him for the execution of the work unsound or of a quality inferior to that contracted or otherwise not in accordance with contract, the Contractor shall on demand in writing from the Estate officer, specifying the work/materials or articles complained of, notwithstanding that the same may have been inadvertently passed, certified and paid for, will rectify or remove and reconstruct the work, so specified, in whole or in part, as the case may be, removed the materials or articles, so specified, and provide other proper and suitable materials or articles, at his own cost and in the even of his failing to do so, within a period to be specified by the Estate officer in his demand, as aforesaid, then the Contractor shall be liable to pay compensation at the rate of one percent on the tendered amount of work for every week, not exceeding ten percent, while his failure to do so shall continue, and in the case of any such failure the engineer-in-charge may rectify or remove and re-execute the work or remove and replace with others, the materials or articles complained of as the case may be, at the risk and expenses. In all respects of the contractor.
Clause 15: Work to be open to inspection: Contractor or his responsible Agent to be present:

All work, under or in course of execution or executed in pursuance of the contract, shall, at all times, be open to inspection and supervision of the Estate officer and his superior officers and his subordinates and any other authorized agency of the University and the contractor shall, at all time during the usual working hours, and at all other times at which reasonable notice of the intention of the Estate officer of his subordinate and any other authorized agency of university committee of retired officer/officer appointed by the university for the purpose to visit the works shall have been given to the contractor, either himself or his agent, duly accredited in writing, present for purpose. Orders given to the Contractor's agent shall be considered to have the same force as if they had been given to the Contractor himself.

Clause 16: Notice to be given before any work in covered up:

The Contractor shall give not less than 7 days notice, in writing, to the Estate officer or his subordinate in charge of the work, before covering up or otherwise placing beyond the reach or measurement any work in order that the same may be measured, and correct dimensions thereof, be taken before the same is so covered up or placed beyond the reach of measurement and shall not cover up or place beyond the reach of measurement any work without the consent in writing of the Estate officer of the work, and if any work shall be covered up or placed beyond the reach of measurement without such notice having been given or consent obtained, the same shall be uncovered at the Contractor's expense or in default, thereof no payment or allowance shall be made for such work, or for the materials, with the same was executed.

Clause 17: Contractor liable for damage done and for imperfections:

If the Contractor or his work people or servants shall break, deface, injure or destroy any part of a building, in which they may be working or any building, road, fence, enclosure, or cultivated ground contiguous to the premises on which the work or any part of its is being executed, or if any damage shall happen to the work, while in progress, from any cause, whatsoever, or any imperfections become apparent in it within a period specified in Clause 37, after a Certificate, final or otherwise of its completion, shall have been given by the Estate officer may cause the same to be made good by other workmen and deduct the expense (of which the certificate of the Engineer-in-charge shall be final) from any sums that may be then, or at any time thereafter, any become due to the contractor, or from his security deposit, or the proceeds of sale thereof, or of a sufficient portion thereof.

Clause 18: Contractor to supply Plant, Ladders, Scaffoldings etc:

The Contractor shall arrange and supply at his own cost, all material (except such special material, if any, as may, in accordance with the contract, be supplied from the Estate officer stores, plants, tools, appliance, implements, ladders, cordage, tackle, scaffoldings and temporary works requisite or proper for the proper execution of the work, whether original, altered, or substituted, and whether included in the specification or other documents, forming part of the contract, or referred to in these conditions or not, or watch may be necessary for the purpose of satisfying on complying with the requirements of the Engineer-in-charge as to any matter as to which, under these conditions, he is entitled to be satisfied of which he is entitled to require, together with carryage thereof, to and from the work. The contractor shall also arrange and supply, without charge, the requisite number of persons with the means and materials, necessary for the purpose of setting out work and counting, weighing and assisting, in the measurement or examination at any time and from time to time of the work, or materials. Failing his doing, the same may be provided by the Estate officer at the expense of the contractor, and the expenses may be deducted from any money due to the Contractor under the contract, or from his Performance Guarantee and or security deposit or the proceeds of sale thereof, or a sufficient portion thereof. The contractor shall also provide all necessary fencing and lights required to protect the public from accident and shall, be bound to bear the expenses of defense of every suit, action or other proceeding at law, that may be brought by any person for injury sustained owing to neglect of the above precautions, and to pay any damages and costs, which may be awarded in any such suit, action proceeding to any such person or which may, with the consent of the Contractor, be paid to compromise any claim by any such person.
Clause 19: Work not be sub-let, Contractor may be rescinded and Security/Deposit and Performance Guarantee Forfeited for subletting, bribing or if Contractor becomes insolvent:

The contract shall not be assigned or sublet without the written approval of the Estate officer, and if the Contractor shall assign or sublet his contract or attempt so to do, or become insolvent, or commence any insolvency proceedings or mark any composition with his creditors, or attempt so to do, or if any bribe, gratuity, gift, loan, requisite reward or advantage, pecuniary or otherwise, shall either, directly or indirectly be given promised of offered by the contractor or any of his servants or agents, to any public officer or person, in the employ of University in any way, relating to his office or employed or if any such office a person shall be cover, in any way, directly or indirectly interested in the contract, the Estate Officer may, thereupon, by notice, in writing rescind the contract and the Performance Guarantee and Security Deposit of the Contractor shall, thereupon, stand forfeited and be absolutely at the disposal of University and the same consequences shall ensue as, if the contract had been rescinded under Clause 3 hereof, and in addition the Contractor shall not be entitled to recover or be paid for any work thereof, actually performed under the contract.

Clause 20: Sums payable by way of compensation to be considered as reasonable compensation without reference to actual loss:

All sums payable by way of compensation under any of these conditions shall be considered as reasonable compensation to be applied to the use of University without reference to the actual loss or damage sustained and whether or not any damage shall have been sustained.

Clause 21: Changes in constitution of firm:

Where the Contractor is a partnership firm, the previous approval, in writing, of the Estate officer shall be obtained before any change is made in the constitution of the firm. Where the Contractor is an individual or a Hindu undivided family business concern, such approval, as aforesaid, shall likewise be obtained before the Contractor enters into any partnership agreement were under the partnership firm would have the right to carry out the work thereby undertaken by the Contractor. If previous approval as aforesaid, is not obtained, the contract shall be deemed to have been assigned in contravention of Clause 19 hereof, and the same action may be taken, and the same consequences shall ensue, as provided in the said Clause 19.

Clause 22: Works to be under direction of Engineer-in-charge:

All the works to be executed under the contract shall be executed under the direction and subject to the approval in all respect, of the engineer-in-charge of the SKUINU for the time being, who shall be entitled to direct at a what print of points or in what manner, they are to be commenced, and from time to time carried on.

Clause 23: Standing Committee for Settlement of disputes:

If any question, difference or objection, whatsoever shall arise in any way, in connection with or arising out of this instrument of the meaning of operation of any part thereof, of the right duties or liabilities of either part then, save in so far, as the decision of any such matter, as herein before provided for, and been so decided, every such matter constituting a total claim of Rs. 50,000/- or above, whether its decision has been otherwise provided for and whether it has been finally decided accordingly or whether the contract should be terminated, or has been rightly terminated, and as regards the rights of obligations of the parties, as the result of such termination, shall be referred for decision of the empowered Standing Committee, which would consist of the followings.

1. Vice Chancellor
2. Comptroller
3. Registrar
4. SE, P.W.D.
5. Estate Officer (Member-Secretary)
The Engineer-in-charge, on receipt of application along with non-refundable prescribed fee, (the fee would be two percent of the amount in dispute, not exceeding Rs. one lac) from the Contractor, shall refer the disputes to the committee within a period of one month from the date of receipt of application.

Procedure and Application for referring cases for settlement by the Standing committee shall be as given in Form RPWA 90.

Clause 23 A: Contractor to indemnify for infringement of Patent or design:
Contractor shall fully indemnify the University against any action, claim or proceeding, relating to infringement or use of any patent or design, or any alleged patent or design rights and shall pay any royalties, which may be payable in respect of any article or part thereof included in the contract, in the event of any claims made under or action brought against University. In respect of any such matters as aforesaid, the Contractor shall be immediately notified thereof, and the Contractor shall be at liberty, at his own expense, so settle any dispute or to conduct any litigation, that may arise there from provided that the contractor shall not be liable to indemnify the SKAU, the Infringement in the patent or design or any alleged patent, or design right is the direct result of an order passed by the Estate officer in this behalf.

Clause 24: Imported Store articles to be obtained from University:
The Contractor shall obtain from the stores of the Estate officer, all imported store articles which may be required for the work or any part thereof or in making up articles required thereof, or in connection therewith, unless he has obtained permission in writing, from the Estate officer to obtain such stores and articles from elsewhere. The value of such stores and articles, as may be supplied to the Contractor by the Estate officer, will be debited to the Contractor, in his account, at the rates shown in the schedule attached to the contract, and if they are not entered in the schedule, they will be debited at cost price which for the purpose of the contract, shall include the cost or carriage and all other expenses, whatsoever which shall have been incurred in obtaining delivery of the same at the stores aforesaid plus storage charges.

Clause 25: Lump-sums in estimates:
When the estimate, on which a tender is made includes lump sums, in respect of parts of the work, the Contractor shall be entitled to payment in respect of the item of work involved, or the part of the work in question at the same rates, as are payable under the contract for such items or if the part of the work in question is not, in the opinion of the Estate officer capable of measurement, the estate officer may at his discretion pay the lump sum amount entered in the estimate and the certificate in writing of the Estate officer shall be final and conclusive with regard to any sum or sums payable to him under the provisions of this clause.

Clause 26: Action where no Specification:
In case of any Class of work for which there is no such specification as is mentioned in Rule 1, such work shall be carried out in accordance with the detailed specification of the department and also in accordance with the instructions and requirement of the Estate officer.

Clause 27: Definition of work:
The expression “works” or “work” where used in these conditions shall, unless there be something either in subject or context, repugnant to such construction, be construed and taken to mean the works by or by virtue of the contract contracted to be executed whether temporary or permanent, and whether original, altered, substituted or additional.

Clause 27 A: Definition of Engineer-in-charge:
The term “Engineer in charge” means the Estate officer who shall supervise and be in charge of the work, and who shall sign the contract on behalf of the vice chancellor SKAU, Jodhpur.

Clause 27 B: Definition of University or SKAU:
The terms university mean Sri Karan Narendra Agriculture University, Jodhpur.
Clause 27 C: Definition of the Vice Chancellor:
The term of vice chancellor means the vice chancellor of Sri Karan Narelda Agriculture University.

Clause 28:
If it cannot be guaranteed that the work will be started immediately after the tenders have been received. No claims for increase of rate will be entertained, if the orders for starting work are delayed.

Clause 29: Payments at reduced rates on account of items of work not accepted and not completed to be at the discretion of the Estate Officer.
The rates for several items of works, estimated to cost more than Rs. 1,000/-, agreed within, will be valid only when the item concerned is accepted, as having been completed fully in accordance with the sanctioned specifications. In cases, where the item of work are not accepted, as so completed, the Estate officer may make payment an account of such items, at such reduced rate as he considers reasonable, in the preparation of final or on account bills, and his decision in the matter shall be final and binding.

Clause 29 A: Payments at part rates:
The rates for several items of works may be paid at part rates provisionally in running bills in proportion to the quantum of item executed at the discretion of the Estate officer. In case of the item rate, if the rate quoted for certain items are very high in comparison to the average/overall tendered premium, then the payment at running stages shall not be made more than the average sanctioned premium. The deferred payment will however be released after successful completion of the work.

Clause 30: Contractor's percentage, whether applied to net or gross amount of bills:
The percentage referred to in the "tender for works" will be deducted/added from/to the gross amount of the bill before deducting the value of any stock issued.

Clause 31: Contractor to adhere to labour laws/regulation:
The Contractor shall adhere to the requirements of the Workmen's Compensation Act and Labour Legislation in force from time to time and be responsible for and shall pay any compensation to his workmen which would be payable for injuries under the Workmen's Compensation Act, hereinafter called the said Act. If such compensation is paid by the University as principal employer under sub section (1) of section 12 of the said act. On behalf of the contractor it shall be recoverable by the SKV/NAU from the Contractor under Sub Section (2) of the said section. Such compensation shall be recovered in the manner laid down in Clause 1 of the Conditions of Contract.

Clause 32: Withdrawal of work from the Contractor:
If the Estate officer shall at any time and for any reasons, whatever, including inability to maintain prorata progress, think any portion of the work should not be executed or should be withdrawn from the contractor, he may, by notice in the writing to that effect, require the contractor not to execute the portion of the work specified in the notice, or may withdraw from the Contractor the portion of work, so specified, and he Contractor shall not be entitled to any compensation by reason of such portion of work having been withdraw from him. The Estate officer may supplement the work by engaging another agency to execute such portion of the work at the cost of the original contractor, without prejudice to his rights under clause 2. He shall also be competent to levy compensation for delay in progress. The recovery of excess cost shall be made from next available running bill or any other claim and shall not be deferred.

Clause 33:
The contract includes clearance, leveling and dressing of site within a distance of 15 meters of the building on all sides except where the building adjoins another building.
Clause 34: Protect works:
The contractor shall arrange to protect, at his own cost, in an adequate manner, all cut stone work and other work, requiring protection and to maintain such protection, as long as work is in progress. He shall remove and replace this protection, as required by the Estate officer from time to time. Any damage of the work, so protected no matter how it may be caused, shall be made good by the Contractor free of cost.

All templates, forms, moulds, centering, false works and models, which in the opinion of the Estate officer are necessary for the proper and workman like execution of the work, shall be provided by the Contractor free of cost.

Clause 35: Contractor liable for settlement of claims caused by his delays:
If the progress of the work has fallen so much in arrears as to prevent other contractors on the work, from carrying out their part of the work within the stipulated time, he will be liable for the settlement of any claim put in by any of these contractors for the expenses of keeping their labour unemployed, to the extent considered reasonable by the Estate officer.

Clause 36 A:
The liability, if any, on account of quarry fees, royalties, octroi and any other taxes and duties in respect of materials actually consumed on public work, shall be borne by the Contractor.

Clause 36 B:
The cost of all water connections, necessary for the execution of work, and the cost of water consumed and hire charges of meters and the cost of electricity consumed in connection with the execution of work, shall be paid by the Contractor, except where otherwise specifically indicated.

Clause 36 C: Payment of Sales Tax, and any other Taxes:
Royalty or other tax on materials, issued in the process of fulfilling contract payable to the Government under rules in force, will be paid by the Contractor himself.

Clause 36 D:
In respect of goods and materials procured by the Contractor for use in works under the contract sales tax will be paid by the Contractor himself. But in respect of all such goods manufactured and supplied by the Contractor and works executed under the contract, the responsibility of payment of sales tax would be that of the Estate officer.

Clause 37: Refund of Security Deposit:
Security Deposit will be refunded after the expiry of the period, as prescribed below:

(a) In case of contracts relating to hiring to trucks and other I & P transportation including the loading and unloading of materials, the amount of Security Deposit is refundable along with the final bill.

(b) Supplies of material: As per provisions of the G.F & A.R.

(c) Ordinary repairs: 3 months after completion of the work provided of final bill has been paid.

(d) Original works/special repairs/renewal works: Security Deposit will be refunded 6 months after completion or expiry of one full rainy season, or after expiry of defect liability period as defined in the special condition of agreement whichever is later provided the final bill has been paid.

(e) In case of original work/special repairs works costing more than Rs. 10 lacs, partial amount or S.D. will be refunded during the period of the liability period @ 10% of S.D. amount after lapse of one year of completion and thereafter 10% of original amount of the S.D. at the end of each subsequent year. The remaining amount of S.D. be refunded after the expiry of defect liability period on a pro-rata order at F.D.'s rate of Int.
Clause 38: Fair Wage Clause:

(a) The Contractor shall pay not less than fair wages/minimum wages to labourers engaged by him on the work as revised from time to time by the government but the University shall not be liable to pay anything extra for it except as stipulated in price escalation clause (clause 45) of the agreement.

Explanation: "Fair Wages" means minimum wages for time or piece work, fixed or revised by the State Government under the Minimum Wages Act, 1948.

(b) The Contractor shall, notwithstanding the provisions of any contract to the contrary, cause to be paid fair wages to labourers indirectly engaged on the work, including any labour engaged by his sub-contractors in connection with the said work as if the labourers had been immediately or directly employed by him.

(c) In respect of all labourers immediately or directly employed on the work for the purpose of the contractor part of his agreement, the Contractor shall comply with or cause to be complied with the Public Works Department Contractor's Labour Regulations made, or that may be made by the Government, from time to time, in regard to payment of wages, wage period, deductions from wages, recovery of wages not paid, and unauthorized deductions maintenance of wages register, wage card, publication of scale of wages and other terms of employment inspection and submission of periodic return and other matters of a like nature.

(d) The State officer shall have the right to deduct from the money due to the Contractor any sum required or estimated to be required for making good the loss suffered by a worker or workers, by reason of non-fulfilment of the conditions of the contract, for the benefit of the worker or workers, non-payment of wages or of deductions made therefrom, which are not justified by the terms of the contract, or as a result of non-observance of the aforesaid regulations.

(e) Vis-a-Vis the "University, the Contractor shall be primarily liable for all payments to be made for the observance of the regulations aforesaid, without prejudice to his right to claim indemnity from his sub-contractors.

(f) The regulations, aforesaid, shall be deemed to be part of this contract and any breach thereof, shall be deemed to be breach of the contract.

Clause 39: Contractor to engage technical staff:

The Contractor shall engage the technical staff, as follows, on the contract works.

(a) For works costing Rs. 100 lacs and above- One Graduate Engineer.

(b) For works costing between Rs. 50 lacs to Rs. 100 lacs- One qualified diploma holder having experience of not less than 3 years.

(c) For works costing between Rs. 15 lacs and Rs. 50 lacs- One qualified diploma holder.

The technical staff should be available at site, whenever required by Engineering-in-charge to take instructions.

Clause 39 A:

The Contractor shall comply with the provisions of the Apprenticeship Act, 1961 and the Rules and Orders issued there under, from time to time. If he fails to do so, his failure will be a breach of contract. The Contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of any violation by him of the provisions of the said Act.

Clause 40: Safety Code:

The Contractor shall follow the safety code of the Department.

Clause 41: Near Relatives barred from tendering:

The Contractor shall not be permitted to tender for works in University in which his near relative is posted as Divisional Accountant or as an officer in any capacity between the grades of the Estate officer and Assistant Engineer (both inclusive). He shall also intimate the names of persons, who are working with him in any capacity or are subsequently employed by him and who are near relatives to any officer in the University. Any breach of this conditions by the Contractor would render him liable to be removed from the approved list of contractors of the Department. If such facts is noticed (a)
before sanction of tender, his offer shall be declared invalid and earnest money shall be forfeited, (b) after sanction of the tender then the tender sanctioning authority may at his discretion forfeit his earnest money, performance guarantee, security deposit and enlistment deposit and the work/remaining work may allot to any registered contractor on the same rates as per rules.

Note: By the term ‘near relative’ is meant wife, husband, parents and grand-parents, children and grand children, brothers and sisters, uncles and cousins and their corresponding in-laws.

Clause 42: Retired Officer barred for 2 years:

No Engineer of Officer rank, employed in Engineering or Administrative duties in Estate office of university is allowed to work as Contractor for a period of 2 years of his retirement from University service without the previous permission of University. The contract is liable to be cancelled, if either the Contractor or any of his employee is found, at any time, to be such a person, who had not obtained the permission of University aforesaid, before submission of the tender or engagement in the contractor’s service, as the case may be.

Clause 43: Quality Control:

The university shall have right to exercise proper Quality Control measures. The Contractor shall provide all assistance to conduct such tests.

Clause 43 A:

The work (whether fully constructed or not) and all materials, tools and plant, scaffolding, temporary buildings and other things connected therewith, shall be at the risk of the contractor until the work has been delivered to the Estate officer and a certificate from him, to the effect, obtained.

Clause 44: Death of Contractor:

Without prejudice to any of the rights or remedies under the contract, if the Contractor dies, the legal heirs of the Contractor of the Vice Chancellor or duly authorized Engineer shall have the option of terminating the contract without any compensation.

Clause 45: Price Variation Clause:

If during the progress of the contract of value exceeding Rs. 50 lac (accepted tendered amount minus cost of material supplied by the department), and where stipulated completion period is more than 6 months (both the conditions should be fulfilled) the price of any materials/bitumen/diesel/petrol/cement and steel incorporated in the works (not being materials to be supplied by the department) and or wages of labour-increases or decreases, as compared to the price and/or wages prevailing at the date of opening of tender or date of negotiations for the work, the amounts payable to contractors for the work shall be adjusted for increase or decrease in the rates of materials (excluding those materials supplied by the department/bitumen/diesel/petrol/cement and steel). If negotiated rates have been accepted, prices as on the date of negotiation shall be considered for price adjustment. Similarly, if rates received on the date of opening of tenders have been accepted then prices on the date of opening of tender shall be considered for price adjustment.

Increase or decrease in the cost of labour/material/bitumen/diesel/petrol cement and steel shall be calculated quarterly in accordance with the following formula:

(A) Labour:

\[ V_l = 0.75 \times \frac{R}{100} \times \frac{k}{k_0} \]

\( V_l \) = Increase or decrease in the cost of work during the quarter under consideration due to change in rates for labour.

\( R \) = The value of the work done in rupees during the quarter under consideration excluding the cost of materials supplied by the department and excluding other items as mentioned in the clause.
\[ \text{LO} = \text{The average consumer price index for industrial workers (wholesale prices) for the quarter in which tender were opened/negotiated (as Reserve Bank of India Journal/Labour Bureau Shimla, for the area).} \]

\[ \text{L} = \text{The average consumer price index for industrial workers (wholesale prices for the quarter of calendar year under consideration (as published in Reserve Bank of India Journal/Labour Bureau Shimla, for the area).} \]

\[ P_l = \text{Percentage of labour components.} \]

Note: In case of revision of minimum wages by the Government or other competent authority, nothing extra would be payable except the price escalation permissible under this clause.

**(B) Material (excluding material supplied by the department).**

\[ V_m = 0.75 \times R \times \frac{B_m - B_o}{L_o} \]

\[ V_m = \text{Increase of decrease in the cost during the quarter under consideration due to change in rates of material.} \]

\[ R = \text{The value of the work done in rupees during the quarter under consideration excluding the cost of materials supplied by the department and excluding other items as mentioned in the clause.} \]

\[ L_o = \text{The average wholesale price index (all commodities) for the quarter in which tenders were opened/negotiated (as published in Reserve Bank of India Journal/Economic Adviser to Government of India, Ministry of Industry for the area).} \]

\[ L = \text{The average wholesale price index (all commodities) for the quarter under consideration (as published in Reserve Bank of India Journal/Economic Adviser to Government of India, Ministry of Industry, for the area).} \]

\[ F_m = \text{Percentage of material component (excluding materials supplied by the Department).} \]

**(C) Bitumen :**

\[ V_b = 0.75 \times R \times \frac{B_b - B_o}{L_o} \]

\[ V_b = \text{Increase of decrease in the cost of work during the quarter under consideration due to change in rates for bitumen.} \]

\[ R = \text{The value of the work done in rupees during the quarter under consideration excluding the cost of materials supplied by the department and excluding other items as mentioned in the clause.} \]

\[ B_o = \text{The average wholesale price for bitumen of the day of opening of tenders/negotiation, as published by the Economic Adviser to Govt. of India, Ministry of Industry.} \]

\[ B_b = \text{The average wholesale price index for bitumen for the quarter under consideration as published weekly by the Economic Adviser, Government of India, Ministry of Industry.} \]

\[ P_b = \text{Percentage of bitumen component excluding bitumen supplied by the Department (Specified in the sanctioned estimate of the work).} \]

**(D) Petroleum :**

\[ V_p = 0.75 \times R \times \frac{F_p - F_o}{L_o} \]

\[ V_p = \text{Increase of decrease in the cost of work during the quarter under consideration due to change in rates for fuel and lubricants.} \]

\[ R = \text{The value of the work done in rupees during the quarter under consideration excluding the cost of materials supplied by the department and excluding other items as mentioned in the clause.} \]

\[ F_o = \text{The average wholesale price Index of POL as published by the Economic Adviser to the Government of India, Ministry of Industry on the day of opening at tender/negotiations.} \]

\[ F_p = \text{The average wholesale price Index of POL for the quarter under consideration as published weekly by the Economic Adviser to the Government of India, Ministry of Industry for the quarter under consideration.} \]

\[ P_p = \text{Percentage of Fuel and lubricants component excluding fuel and Lubricants supplied by the Department (Specified in the sanctioned estimate for the work).} \]

\[ R = \text{Total work done during the quarter as prescribed under this clause.} \]

Note : For application of this clause price of POL in chosen to indicate fuel and lubricant component.
(E) Cement:

\[ V_E = 0.75 \times \frac{P_E}{L_0} \times R \times \frac{L_{w1} - L_{w2}}{L_{w2}} \]

\( V_E \) = Increase of decrease in the cost of work during the quarter under consideration due to change in rates of cement.
\( R \) = The value of the work done in rupees during the quarter under consideration excluding the cost of cement supplied by the department and excluding other items as mentioned in the clause.
\( L_{w1} \) = The average wholesale price index for the quarter in which tenders were opened/negotiated (as published by the Economic Adviser to Government of India, Ministry of Industries).
\( L_{w2} \) = The average wholesale price index for the quarter under consideration (as published by the Economic Adviser to Government of India, Ministry of Industries).
\( P_E \) = Percentage of cement components (excluding cement supplied by the Department).

(F) Steel:

\[ V_I = 0.75 \times \frac{P_I}{L_0} \times R \times \frac{L_{w1} - L_{w2}}{L_{w2}} \]

\( V_I \) = Increase of decrease in the cost of work during the quarter under consideration due to change in rates of steel.
\( R \) = The value of the work done in rupees during the quarter under consideration excluding the cost of steel supplied by the department and excluding other items as mentioned in the clause.
\( L_{w1} \) = The average wholesale price index for the quarter in which tenders were opened/negotiated (as published by the Economic Adviser to Government of India, Ministry of Industries).
\( L_{w2} \) = The average wholesale price index for the quarter under consideration (as published by the Economic Adviser to Government of India, Ministry of Industries).

Clause 45 A: Price Variation in installation of elevators, supply/Installation of Centrally Air Conditioning and Central Evaporating Cooling Works:

In all cases of contracts for installation of elevators, supply/Installation of Central Air Conditioning and Central Evaporating Cooling Works, the Price quoted shall be based on the Indian Electrical and Electronic Manufacturers Association (IEEMA) Price variation clause based on the cost of raw materials/components and labour cost as on the date of quotation tender, and the same is deemed to be related to wholesale price index number of metal products and A India Average consumer price index number of industrial workers as specified below. In case of any variation in these index numbers, the prices shall be adjustment up or down in accordance with following formula:

\[ P = \frac{P_0}{100} \left[ 15 + 55 \left( \frac{M_{w1}}{M_{w2}} \right) + 15 \left( \frac{W_{w1}}{W_{w2}} \right) \right] \]

Where
\( P \) = Price payable as adjusted in accordance with the price variation formula.
\( P_0 \) = Price quoted/confirmed.
\( M_{w1} \) = Wholesale Price Index Number for metal products as published by the office of the Economic Adviser, Ministry of Industry, Government of India, in their weekly bulletin, Revised Index Number of Wholesale Price (Base : 1981-82 = 100 for the week ending first Saturday of the relevant calendar month. The relevant month shall be that in which price was offered or negotiated whichever is later.
\( W_{w1} \) = All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers (Base : 1982 = 100), as published by Labour Bureau, Ministry of Labour, Government of India, for relevant calendar month. The relevant month shall be that in which price was offered or negotiated whichever is later.

The above Index number \( M_{w1} \) & \( W_{w1} \) are those published by IEEMA as prevailing of the first working day of the calendar month. Four month prior to the date of tendering.

\( M_w \) = Wholesale Price Index Number of Metal Products as published by the office of Economic Adviser, Ministry of Industry, Government of India, in their weekly bulletin Revised Index Number of wholesale price (Base : 1981-82 = 100)
The applicable wholesale Price Index Number for Metal Products as prevailing on 1st Saturday of the Month covering the date FOUR months price to the date of delivery and would be as published by IEEMA.
\[ W_c = \text{All India Average Consumer Price Index Number for industrial workers (Base: 1982 = 100)} \]

as published by Labour Bureau, Ministry of Labour, Government of India. The applicable All India Consumer Price Index Number of industrial workers prevailing for the FOUR months prior to the date of completion of installation/progress parts of installation are would be as published by IEEMA. The date of delivery shall be the date on which the manufactured material is actually supplied at site. The date of completion of installation (or progress part of installation shall be the date of which the work in notified as being completed and is available, for inspection/duty tested), In the absence of such notification, the date of completion is not intimated, such completion shall be considered by the Engineer-in-charge which shall be final.

Note 1 The Wholesale Price Index Number for number for Metal, Products is published weekly by the office of the Economic Adviser, but if there are changes, the same are incorporated in the issue appearing in the following week. For the purpose of this price variation Clause, the final index figures shall apply.

Note 2 The sole purpose of the above stipulation is to arrive at the entire contract under the various situations. The above stipulation does not indicate any intentions to sell materials under this contracts as moveables.

Note 3 The indices \( M_p \) & \( W_c \) are regularly published by IEEMA in monthly basic price circulars based on information bulletins from the authorities mentioned. These will be used for determining price variation and only IEEMA Circulars will be shown as evidence, if required.

General Conditions for Admissibility or Escalation

1. The exact percentage of labour/material excluding materials to be supplied by the department/bitumen/diesel petrol, cement, steel component and labour for the work shall be approved by the authority while scrutinizing the detailed Estimates.

2. The break-up of components of labour/materials (excluding materials to be supplied by the department/bitumen diesel) and petrol cement steel as indicated in Clause 45 have been pre-determined as below:

   (a) Labour ................................................................. Percent
   (b) Material ............................................................... Percent
   (c) Bitumen ................................................................. Percent
   (d) Diesel and Petrol (POL) .......................................... Percent
   (e) Cement ................................................................. Percent
   (f) Steel ................................................................. Percent

   Total ........................................................................

3. While allowing price escalation the following shall be deducted from the value of work done (R): (a) Cost of material supplied by the Department (b) Cost of services rendered as per clause 34, (c) of Secured Advance/ any advance added earlier but deducted agreed rates.

4. The first statement of escalation shall be prepared at the end of three months in which the work was awarded and the work done from the date of start to the end of this period shall be taken into account. For subsequent statement cost of work done during every quarter shall be taken into account. At the completion of work done during the last quarter of fraction thereof shall be taken into account.

5. For the purpose of reckoning the work done during any period, the bills prepared during the period shall be considered. The dates of recording measurements in the Measurement Book by the Assistant Engineer shall be the guiding factor to decide the bills relevant to any period. The date of completion, as finally recorded by the competent authority in the Measurement Book shall be the criterion.

6. The index relevant to any quarter for which such compensation is paid, shall be the arithmetical average of the indices relevant of the calendar month.

7. Price adjustment clause shall be applicable only for the work that is carried out within the stipulated time or extension thereof, as are not attributable to the contractor.

8. If during the progress in respect of contract works stipulated to cost Rs. 50 lac or less the value of work actually done excluding cost of material supplied by the Department exceeds Rs. 50 lac and completion period is more
than 6 months, then escalation would be payable only in respect of value of work in excess over Rs. 50 lac from the date of satisfying both the conditions.

9. Where originally situated period is 6 months or less but actual period of execution exceeds beyond 6 months or account of reasons not attributable to contractor, escalation amount would be payable only in respect of extended period if amount of work is more than Rs. 50 lac.

10. In case the contractor does not make proper progress in the first or another time span and the short fall in progress in covered up by him curing subsequent time span within original stipulated period then the price escalation of such work expected to be done in the previous time span shall be nationally given based upon the price index of that quarter in which such work was required to be done.

11. No claims for price adjustment other than those provided herein, shall be entertained.

12. If the period of completion period attributable to Government exceeds twelve months but cost does not exceed more than Rs. 50 lac no escalation is admissible.

13. Similarly, if cost of works increases more than Rs. 50 lac but completion period including extended period attributable to Government is less than 6 months, no escalation is admissible.

14. No provisional escalation is payable on the basis of indices of the previous quarter in absence of non publication of Indices for concerned quarter by the RBI.

15. Escalation is always payable quarterly and no provisional escalation is payable monthly or fortnightly.

16. In case at the time of executing agreement both the condition (completion period 6 months and amount of work Rs. 50 lac) for admissibility of price escalation are not fulfilled and subsequently due to additional work and extension of time attributable to Government, both the conditions become fulfilled in that case the escalation shall be payable from the date of satisfying both the conditions and only for work done beyond Rs. 50 lac and in period of work beyond 6 months.

The contractor shall for the purpose of this conditions keep such books of account and other document as are necessary to show the amount of any increase climbed or reduction available and shall allow inspection of the same by a duly authorized representative of Government and further shall at the request of the Engineer-in-charge furnish verified in such a manner as the Engineer-in-charge may require.

Clause 46: Force Majeure:

Neither party shall be liable to each other, for any loss or damage, occasioned by or arising out of acts of God such as unprecedented floods, volcanic eruptions, earthquake of other invasion of nature and other acts.

Clause 47: General Discrepancies and errores:

In case of percentage rate tenders, if there is any typographical or clerical error in the rates shown by the department in the "G" Schedule, the rates as given in the basic Schedule of Rates of the Department for the area shall be taken as correct.

Clause 48: Post Payment Audit & Technical Examination:

The Government shall have right to cause an audit and technical examination of the works, and the final bills of the as a result of such audit and technical examination, any sum is found to have been over paid in respect of any work done by the Contractor under the contract or any work claimed by him to have been done by him under the contract and found not to have been executed below specification, the Contractor shall be liable to refund the amount of over payment and it shall be lawful for department to recover the same from him in the manner prescribed in Clause 50 or in any other manner legally permissible and if it is found that the contractor was paid less than what was due to him under the contract or respect of any work executed by him under it, the amount of such under payment shall be duly paid by the university to the Contractor.
Clause 48 A: Pre Check or Post Check or Bills:

The University shall have right to provide a system of pre-check of Contractor's bills by a specified Organization and payment by an Engineer or an Accounts Officer/Sr. Accounts Officer / Chief Accounts Officer / Financial Advisor, as the University may in its absolute discretion prescribe. Any over-payment / excess payment detected, as a result of such pre-check or post-check of Contractor's bills, can be recovered from the contractor's bills in the manner, hearing before provided and the Contractor will refund such over/excess payments.

Clause 48 B: Check Measurement:

The department reserves to itself, the right to prescribe a scale of check measurement of work in general, or specific scale for specific works or by other special orders (about which the decision or the department shall be final) Checking of measurement by superior officer shall supersede measurements by the subordinate officer and the former will become the basis of the payment. Any over / excess payment detected, as a result of such check measurement or otherwise at any stage up to the date of completion and the defect removal period specified elsewhere in this contract, shall be recoverable from the Contractor, as any other dues payable to the university.

Clause 49: Dismantled Materials:

The Contractor in course of the work, should understand that all material e.g. stone, bricks, steel and other materials obtainable in the work by dismantling etc. will be considered as the property of the university and will be disposed of to the best advantage on the university. As per instruction of the Engineer-in-charge.

Clause 50: Recovery from Contractors:

Whenever any claim against the Contractor for the payment of a sum of money arises out of or under the contract, the Department shall be entitled to recover such sum by appropriating in part or whole of the Performance Guarantee and / or security deposite, security deposite at the same time enlilment of the contractor. In the event of security being in sufficient or if no security has been taken, thereafter, may become due to the Contractor, under this or any other contract with the university. Should this sum be not sufficient to cover the full amount recoverable the Contractor shall pay to the Department on demand the balance remaining dues.

The department shall, further, have the right to effect such recoveries under Public Demands Recovery Act.

Clause 51: Jurisdiction of Court:

In the event of any dispute arising between the parties hereto, in respect or any of the matters comprised in this agreement, the same shall be settled by a competent court having jurisdiction over the place, where agreement is executed any by no other court, after completion of proceedings under Clause 25 of this contract.
<table>
<thead>
<tr>
<th>S. No.</th>
<th>Particulars</th>
<th>Quantity</th>
<th>Rates</th>
<th>Place of Delivery</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Unit</td>
<td>Rupees</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Schedule of Material to be Supplied by the Department; If available (Refered to in Clause 10)
Schedule of Machinery / T&P to be supplied by the Department

The following Machinery & P shall be supplied by the Department, if available, to the Contractor on hire as per "Rules of the Department" for supply for machinery and T&P to the Contractors on hire (Refer to in Clause 1 OC)

<table>
<thead>
<tr>
<th>S. No.</th>
<th>Item</th>
<th>Rates</th>
<th>Place of Delivery</th>
</tr>
</thead>
</table>

29
## Progress Statement referred to in Clause 2 of Conditions of Contract

<table>
<thead>
<tr>
<th>Name of Work</th>
<th>Date from which the work should be commenced</th>
<th>Date by which the work should be completed</th>
<th>Monthly rate of Progress</th>
</tr>
</thead>
</table>

---

The Contractor has been informed that this tender has been accepted.

Dated........................Signature of Estate officer

Dated........................Signature of Contractor
Notes: For filling in the progress Statement Form

1. Columns 2, 3 and 4 must be initialed and dated by the Contractor.

2. Column 4 must be initialed and dated by the Estate officer or other duly authorized Engineer also.

3. The date in column 2 should correspond to the date on which the order to commence work is given to the contractor read with Clause 2 of the conditions of contract.

4. The date in column 3 must correspond to the period stated in Sub Clause (e) of the Memorandum below "Tend for works."

5. Column 4. This will ordinarily be worked out proportionately; thus if Rs.21,000/- is the cost of the whole or part of work tendered for, and six months period of completion, then the monthly rate of progress should be Rs. 4,000 - if necessary quantities may also be specified in this column at the discretion of the Estate officer.

6. The Certificate as to intimation of acceptance of tender printed at the foot of the form, must be signed and dated both by the Estate officer or other duly authorized Engineer and the Contractor.
ANNEXURE TO APPENDIX XI

SRI KARAN NARENDRA AGRICULTURAL UNIVERSITY CONTRACTORS
LABOUR REGULATIONS

1. **Short title:** These regulations may be called "The Sri Karan Narendra Agriculture University Contractors' Labour Regulations."

2. **Definition:** If these regulations unless otherwise expressed or indicated, the following words and expressions shall have the meaning hereby assigned to them respectively, that is to say:

   (i) **Labour** means workers employed by a Swami Keshvanand Rajasthan Agricultural University contract directly, or indirectly through a subcontractor or other person or by an agent on his behalf.

   (ii) **Fair Wage** means minimum wages for time or piece work fixed or revised by the State Government under the Minimum Wages Act, 1948.

   (iii) **Contractor** shall include every person whether sub-contractor or headman or Agent employing labour on the work taken on contract.

   (iv) **Wages** shall have the same meaning as defined in the Payment of Wages Act and includes time or piece rate wages.

3. **Display of Notice regarding wages etc.:** The contractor shall (a) before he commences his work on contract display and correctly maintain and continue to display and inconspicuous places on the work notices in English and the correctly maintain in Hindi by the majority of the workers giving the rate of wages which have been certified by the Estate Officer or Labour Commissioner, as fair wages and the hours of works for which such wages are earned, and (b) send a copy of such notices to the Certifying Officers.

4. **Payment of Wages:**

   (i) Wages due to every worker shall be paid to him direct.

   (ii) All wages shall be paid in current coin or currency or in both.

5. **Fixation of wage periods:**

   (i) The contractor shall fix the wage periods in respect of which the wages shall be payable.

   (ii) No wage period shall exceed one month.

   (iii) Wages of every workman employed on the contract shall be paid before the expiry of ten days after the last day of the wage period in respect of which the wages are payable.

   (iv) When the employment of any worker is terminated by or on behalf of the contractor, the wages earned by him shall be paid before the expiry of the day succeeding the one of which his employment is terminated.

   (v) All payment of the wages shall be made on a working day except when the work is completed before the expiry of the wage period, in which case, final payments shall be made within 48 hours of the last working day.

**Note:** The term "working day" means a day on which the labour is employed in progress.

6. **Wage Book and Wage slips etc.:**

   (i) The Contractor shall maintain a Wage Book of each worker in such form as may be convenient but the same shall include the following particulars:

      (a) Rate of daily or monthly wages.

      (b) Nature of work on which employed.

      (c) Total number of days worked during each wage period.

      (d) Total amount payable for the work during each wage period.

      (e) All deductions made from the wages with an indication in each case of the ground for which the deduction is made.

      (f) Wages actually paid for each wage period.

      (g) The contractor shall also maintain a wage slip for each worker employed on the work.

      (h) The Estate Officer may grant an exemption from the maintenance of the wage books and wage slips to a contractor who, in his opinion, may not directly or indirectly employ more than 50 persons on the work.
7. Fines and deductions which may be made from wages:
   (i) The wages of a worker shall be paid to him without any deductions of any kind except those authorized, namely the following:
      (a) Fines.
      (b) Deductions for absence from duty i.e., from the place or places where, by the terms of his employment, he is required to work. The amount of deduction shall be in proportion to the period for which he was absent.
      (c) Deductions for damages to or loss of goods expressly entrusted to employed person for custody or for loss or any other deductions of money, which he is required to account where such damages or losses are directly attributable to his neglect or default.
   (i-h) The University may, from time to time, allow deductions other than those specified in clause 1 above.
   (ii) No fines shall be imposed on a worker and no deductions for damage or loss shall be made until worker has been given an opportunity of showing cause against each fine or deductions.
   (iii) The total amount of fines, which may be imposed in any one wage period on a worker, shall not exceed an amount equal to three paise in rupee of the wage payable to him in respect of that wage period.
   (iv) No fine imposed on any worker shall be recovered from him by instalments or after the expiry of 60 days from the date on which it was imposed.

8. Register of fines etc.: The contractor shall maintain a register of fines and of all deductions for damage or loss. Such register shall mention the reasons for which fine was imposed or deduction for damage or loss was made.

   The Contractor shall maintain both in English and local Indian language, a list approved by the Labour Commissioner clearly stating the acts and omission for which penalty of fine may be imposed on a workman and display it in a good condition in a conspicuous place on the work.

9. Preservation of Register: The wage register, the wage card and the register fines deductions required to be maintained under these regulations, shall be preserved for 12 months after the date of the 1st entry made in them.

10. Powers of Labour Welfare Officer to make investigation of enquiry: The Labour Welfare Officer or any other person, authorized by the State Government on their behalf, shall have power to make enquires with a view to ascertaining and enforcing due and proper observance of the fair wage clauses and provisions of the fair wage clauses and provisions of the regulations. He shall investigate into any complaint regarding default made by the Contractor or Sub-Contractor in regard to such provisions.

11. Report of Labour Welfare Officer: The Labour Welfare Officer or other person, authorized as aforesaid, shall submit a report of the result of his investigation or enquiry of the Estate Officer concerned indicating the extent, if any, to which the default has been committed with a note that necessary deductions from the contractors bill be made and the wage and other dues be paid to the labour concerned in case an, appeal is made by contractor under clause 12 of these regulations, actual payment to Labours will be made by the Estate Officer after the Labour Commissioner had given decision on Such appeal.

12. Appeal against the decision of Labour Welfare Officers: Any person aggrieved by the decision and recommendation of the Labour Welfare Officer or other persons, so authorized, may appeal against such decision to the Labour Commissioner within 30 days from the date of decision forwarding simultaneously a copy of his appeal to the Estate officer concerned but subject to such appeal the decision of the Officer shall be final and binding upon the contractor.

12-A No party shall be allowed to be represented by a lawyer during any investigation, enquiry, appeal or any other proceedings.

13. Inspection of Wages Books and Slips: The Contractor shall allow inspection of the wage books and wage slips and register of fines and deductions to any of his workers or to his agent at a convenient time and place after due notice in received or to the Labour Welfare Officer or any other person authorized by the State Government on his behalf.

14. Submission of Return: The Contractor shall submit periodical returns, as may be specified from time to time.

15. Amendments: The State Government may, from time to time, add to or amend these regulations and on any questions as to the application, interpretational effect of these regulations, the decision of the Labour Commissioner to the Government of Rajasthan or any other person authorized by the State Government in that behalf, shall be final.
**SCHEDULE OF FAIR WAGE TO BE GIVEN BY ESTATE OFFICER, LIST OF ACTS AND COMMISSIONER FOR WHICH FINE CAN BE IMPOSED**

1. Wilful insubordination or disobedience whether alone or in combination with another.
2. The fraud or dishonesty in connection with the contractors' business or property of the University.
3. Taking or giving bribes or any illegal gratification.
4. Habitual late attendance.
5. Drunkenness, fighting, riot or disorderly or indecent behavior.
6. Habitual negligence.
7. Smoking near or around the area where combustible or other materials are stored.
8. Habitual indiscipline.
9. Causing damage work in progress or to property of the university or the contractor.
10. Sleeping on duty.
11. Malingering or showing down work.
12. Giving of false information regarding name, age, father's name.
13. Habitual loss of wage cards supplied by the employers.
14. Unauthorized use of employer's property or manufacturing or making of unauthorized articles at the work places.
15. Bad workmanship in construction and maintenance by skilled workers which is not approved by the department and for which contractors are compelled to undertake rectification.
16. Making false complaints and/or misleading statement.
17. Engaging, in trade within the premises of the establishment.
18. Any delinquency of business affairs of the employers.
19. Collection or canvassing for the collection of any money within the premises of an establishment unless authorized by the employer.
20. Holding meeting inside the premises without previous sanction of the employer.
21. Threatening or intimidating any workman or employee during the working hours within the premises.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Particulars</th>
<th>Rates which the materials will be charged to the contractor</th>
<th>Place of Delivery</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Doors, with Chowkhas</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Doors, with Chowkhas</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Doors, with Chowkhas</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Windows with Chowkhas</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Windows with Chowkhas</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Windows with Chowkhas</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Steel Shapes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Steel Shapes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Steel Shapes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bars Mild Steel</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sheets plain, G.I.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sheets plain, Corrugated G.I.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Girting, Wire</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Belts Tower</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Belts Tower</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Locks, Mortice</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Locks, Mortice Rim</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hinge, Butt</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hinge, Butt</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hinges, Spring</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cement, Portland</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Note: The person or firm submitting the tender should see that the rates in the above schedule are filled up by the Engineer in charge of the issue of the form prior to the submission to the tender.

(Signature of Contractor)  (Signature of Engineer)
Progress Statement referred to in Clause 3 of Conditions of Contract

<table>
<thead>
<tr>
<th>Name of Work</th>
<th>Date from which the work should be commenced</th>
<th>Date by which the work should be completed</th>
<th>Monthly rate of Progress</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

The Contractor has been informed that his tender has been accepted.

Date: 
Engineer in charge/Estate officer

Date: 
Contractor

NOTES FOR FILLING IN THE PROGRESS STATEMENT FORM ON THE LAST PAGE

1. Columns 2, 3 and 4 must be initialed and dated by the contractor.
2. Column 4 must be initialed and dated by the Estate officer or other duly authorized Engineer also.
3. The date in column 2 should correspond to the date on which the order to commence work is given to the contractor, specified in line 3, clause 2, page 3 of the "condition of contract".
4. The date in column 3 must correspond to the period stated in clause (1) page 2, of the tender.
5. Column 4, This will ordinarily be worked out proportionately; thus if Rs. 24,000/- is the cost of the whole portion of work tendered for, and six months period of completion, then the monthly rate of progress should be Rs. 4,000. If necessary, quantities may also be specified in this column at the discretion of the Estate officer.
6. The certificate as to intimation acceptance of tender printed at the foot of the form, must be signed and dated both by the Estate officer or other duly authorized Engineer and the contractor.
<table>
<thead>
<tr>
<th>S.No.</th>
<th>Gross Amt. of Bill</th>
<th>Progressive Total Amt. of Bill</th>
<th>Materials 10sq.</th>
<th>Quantity Hours</th>
<th>Amount</th>
<th>S.D.</th>
<th>Income tax deduction</th>
<th>Sales Tax</th>
<th>Royalty</th>
<th>Other Recoveries</th>
<th>Total Recoveries</th>
<th>Net Amount of Payment</th>
<th>C.B.Vr.No. &amp; Date</th>
<th>D.A.O.</th>
<th>E.O.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4(a)</td>
<td>4(b)</td>
<td>4(c)</td>
<td>4(d)</td>
<td>4(g)</td>
<td>4(h)</td>
<td>4(i)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4(l)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
राजस्थान सरकार
कित्त (जी. एण्ड टी.) विभाग

केमैक. एफ.1(फ)दिल /सतिलेगि /2011

जयपुर. दिनांक 4 फरवरी, 2013
परिपार्श । - 7/2013

परिपार्श

पूर्वांक बौद्धिक विद्या है राजस्थान सरकार में जारी आयोजन दिनांक 24.01.2013 द्वारा राजस्थान लोक उपाध्य एवं परदर्शिता आयोजन, 2012 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012) एवं राजस्थान लोक उपाध्य एवं परदर्शिता नियम, 2013 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013) राज्य में दिनांक 28.01.2013 से प्रभावी हो गये हैं। समस्त उपाध्य संस्थाएँ (Procurement Entities) जिनमें राज्य सरकार को समस्त विभाग, सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई भी राज्य राजकीय सेक्टर उद्योग, संबंधित अन्य स्थापना या गठबंधन कोई भी निकाय जिसके योग की पूरी राज्य की संयुक्त निधि से की जाती है, राज्य सरकार स्वरूप में किसी अभियोजन द्वारा स्थापित या गठित कोई निकाय या बैठक या निगम या प्रशिक्षणक्षेत्र या संसाधनों या व्यापार या स्थायी नियोजन या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई निकाय, संयुक्त है, उसके द्वारा लागू होने वाले उपाध्य (Procurement) के नामों में उक्त अभियोजन एवं नियमों की अक्षरपल्लि सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

उक्त अभियोजन की धारा 50 के अन्तर्गत राज्य उपाध्य स्वाक्षर प्रक्रिया (State Procurement Facilitation Cell) का गठन किया जा चुका है। उक्त प्रक्रिया का मुद्दा अधिकारी, संबंधित सैद्धांतिक विभाग (जी.एम.डी.) विभाग के निमित्त गठित किया गया है विकसन उपाध्य संस्था उक्त अभियोजन एवं नियमों के संदर्भ में कोई अनुपालन नहीं रखते हैं तो प्रशासनिक विभाग के साधन से प्रकार राज्य उपाध्य स्वाक्षर प्रक्रिया को प्रेषित किया जा सकता है।

उक्त अभियोजन की धारा 17 में दिये गये उपाध्य के तहत राज्य ऑनलाइन उपाध्य पोर्टल (http://sppp.raj.nic.in) बना दिया गया है। उपाध्य संस्था अभियोजन की धारा 17 (2) एवं राजस्थान लोक उपाध्य एवं परदर्शिता नियम, 2013 के प्राधिकृतों के अनुसार पालना सुनिश्चित कराएं।
उक्त अधिनियम के अध्याय 3 एवं नियमों के अध्याय 7 के अनुसार बोली लगाने वाला या नामी 
बोली लगाने वाला (bidder or prospective bidder) उपयोग प्रक्रिया के दौरान उपयोग संस्था के किसी निर्माण, कर्मवाही या लोग, इस अधिनियम या इसके अभिन्न जारी नियमों के उपयोग की उल्लंघन में है तो यह अपील राखिल कर सकता। इस संबंध में बोली दस्तावेजों, पूर्व अर्जित दस्तावेजों, राजमार्गिक दस्तावेजों ने उपयोग अपील अधिकारी का प्रतिविन्दित (designated) सिद्धिविद्ध (specified) उपयोग उपयोग संस्था द्वारा किया जाना आवश्यक है। अतः, अधिनियम की धारा 3 (2) में उल्लिखित तमत 
सिद्धिविद्ध / संगठन अपने स्थान पर प्राप्त अपील अधिकारी का निर्धारण कर विभाग को दिनांक 15 
फरवरी, 2013 तक सुनिश्चित करें। यहाँ यह उल्लिखित करना उपयुक्त होगा कि प्राप्त अपील अधिकारी 
उपयोग संस्था द्वारा एक तरह उच्च होना आवश्यक है। द्वितीय अपील अधिकारी राज्य सरकार के विभागों 
के लिए संबंधित प्राधिकारिक सिद्धिविद्ध होगा। वही प्राधिकारिक सिद्धि प्राप्त उपयोग संस्था वा प्राप्त अपील 
अधिकारी है तो विभाग सिद्धि। द्वितीय अपील अधिकारी होगा। ऐसे मामलों में तहरी विभाग 
प्राप्त अपील अधिकारी है तो द्वितीय अपील अधिकारी करार के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 
प्रतिविन्दित (designated) किया जाएगा।

उक्त अधिनियम के अनुसार सामग्री, सेटा, संकल्पना के उपयोग के लिए स्टेडियम विभिन्न 
डेमांडडरदार प्रक्रियाधीन है। अधिनियम की धारा 59 (Savings) के अनुसार इस अधिनियम में उपयोग 
सामग्री, सेटा एवं संकल्पना के उपयोग के लिए संबंधित सभ्य नियम, विनियम, आदेश, अभिन्न जारी, विभागीय 
सहित, निर्देशिकाएं, उपविधियां, राजस्वीय कायम या अन्य जो इस अधिनियम के प्रारूप की तारीख 
को प्रभाव करें। हमने इस अधिनियम का उपयोग से संबंधित होने की तीमत, अत: तक प्रस्तर करेंगे 
जब तक कि उनकी इस अधिनियम के अभिन्न जारी या जारी किये गए नियम, मानविक अधिकृत 
अभिन्न जारी या उपविधियां आपसे निर्मित तथा अप्रतिम नहीं कर दिया जाता। अतः, उक्त 
अधिनियम एवं नियमों के अनुसार सामग्री, सेटा, संकल्पना के उपयोग के लिए विभाग प्रतिविन्दित विभिन्न 
संस्थाओं के लिए उल्लिखित प्रति 14, 15, 16 और 17 तथा संकल्पना के 
संशोधन के लिए संबंधित निर्माता विभिन्न एवं लेखा नियम के अधिकार XI में दिए। गए विभाग 
प्रतिविन्दित दस्तावेज बोली दस्तावेजों के रूप में अधिनियम व नियमों के प्रतिविन्दित की सीमा तक प्रयोग नियंत्रित जा सकते, जब तक कि नवीन स्टेडियम विभिन्न डेमांडडरदार जारी नहीं किये जाते है। विभिन्न 
निर्माता संगठन (Annexures) विभाग प्रतिविन्दित बोली दस्तावेजों के साथ सम्मिलित करते 
हुवे ही विभिन्न दस्तावेज जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाये—  

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest 
Annexure B : Declaration by Bidders regarding Qualifications

Doc!
Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process
Annexure D : Additional Conditions of Contract

अनुदान प्राप्ति के लिए सरकारी समस्त स्वामी, कार्यालय एवं संगठनों से अवलोकन की कार्रवाइ के
संबंध में निर्देशित करते हैं।

संज्ञान : Annexure A to D

प्रतिशिंगिनि निर्देशित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित हैं-
1. निजी सचिव, रज्जुनाथ/मुख्य सचिव, संसार मंत्री/राज्य मंत्री।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/संसार मंत्री/राज्य मंत्री शासन सचिव/संसार मंत्री शासन सचिव/संसार
   विकास शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त संविधान, राजस्थान, जयपुर।
5. विलिं, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रेटर, राजस्थान लोक न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
7. संसार निधि शासन सचिव/अभिभावक शासन सचिव/संविधान के संसार अनुग्रह/विभाग।
8. शासन महालेखाकार (शहीद सेना परीक्ष) राजस्थान, जयपुर।
9. महालेखाकार (प्रति एवं प्रशिक्षक लेखा परीक्ष)।
10. संसार विभागव्यवस्था/कलेक्टर विभाग/समानीय अवधि।
11. रजिस्ट्रेटर, राजस्थान लोक सेवा अधिकारी, जयपुर।
12. संसार निधि शासन।
13. सिस्टम एनालिस्ट, विभाग विभाग को मेल जारी लेख है कि विकल्प की जो दिलीप शिप्क की वेल्सा०ट पर प्रकाशित करने
   की आवश्यकता है।

(चित्तला पॉली) परिधिक शासित
Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process,
(g) disclose conflict of interest, if any; and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
   a. have controlling partners/shareholders in common; or
   b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
   c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
   d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
   e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
   f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
   g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.
Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .................................. for procurement of .................................. in response to their Notice Inviting Bids No. ...............

Dated ............... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date: ......................................................... Signature of bidder
Place: ..........................................................
Name: ..........................................................
Designation: .................................................
Address: ......................................................
Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ______________________
The designation and address of the Second Appellate Authority is ______________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose of it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:
(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal
(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal
(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall
   (i) hear all the parties to appeal present before him; and
   (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.
FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. .......... of ............

Before the ................. (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

   .......................................................... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

   ........................................................................................................

Place ...........................................................

Date ..........................................................

Appellant's Signature

Doc.
Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected,

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Security Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.
3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.
Office of the Chief Engineer, P.W.D., Rajasthan

Date:

Office Order

In partial modification to the Order no. CH(Bldg)/DLP(Bldg)R dated 10.09.2012, the Defect Liability Period (DLP) for New Building Special Repair to Building works shall be Three Years for the defect in Building Structure and other civil works. Special conditions in Agreement to this effect shall be as per Annexure 'I' which shall be modified agreement/tender document.

This bears the approval of Govt. ID No. 1664/M/PWD/12 dated 21.06.2012.

This order shall be effective from date of issue.

Encl.-Special Conditions of Contract

(HAZARI LAL MEH)
Chief Engineer cum Addl. Addl., PWD, Rajasthan

No. CH(Bldg)/DLP(Bldg)R Works)/D-

Copy submitted/ forwarded to the following for information and necessary action:

1. P.S. to Pr. Secretary to CM, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
2. P.S. to Hon'ble Minister, PWD, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
3. P.S. to Hon'ble State Minister, PWD, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
4. D.S. to Chief Secretary, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
5. P.S. to Principal Secretary, F.D., Govt. of Rajasthan, Jaipur.
6. P.S. to Principal Secretary, PWD, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
7. Pr. Secy., Secretaries to GoR. (All) for circulation to Organizations under their control.
8. P.S. to Secretary, PWD, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
9. Commissioner, Rajasthan Housing Board/AHS Vikas Sansthan, Jaipur.
10. Commissioner JDA, Jaipur (IIDA Incharge)NN, Jaipur.
11. Managing Director, RIDCO, Jaipur.
12. Manager, AAI, Jaipur.
13. Chief Engineer.— (All).
14. Managing Director, RS/DDC Jaipur with the direction to implement DLP from 24.09.2012
15. FA, PWD, Rajasthan, Jaipur.
17. Chief Engineer, RHEDP, Medical Department, Raj. Jaipur.
18. Chief Engineer, DPEP, Education Department, Raj. Jaipur.
19. Superintending Engineer, PWD, Circle— (All).
20. T/A/JEF (Roads)/BOT/TR/PMGSY/NH/Buildings/SS.
21. Executive Engineer, PWD, Dn— (All).
22. ACP/Section-II/Engineer L.R./DS.
23. President, Contractors' Association, Jaipur.

(HAZARI LAL MEH)
Chief Engineer cum Addl. Addl., PWD, Rajasthan Jaipur.
Special Conditions of contract regarding Defect Liability Period for works.

Civil Works:

Defect liability period for Building structure and other Civil works 3 years reckoned from date of actual completion of the Building. 2 years for the defects pertaining to Sanitary works, Electrical, Joinery works & Painting works. Generally, following defects for D.L.P.

1. Surface cracks on R.C.C. work.
2. Cracks in masonry, walls, pillars, etc.
3. Dampness appeared on surface of wall, ceiling, floors, etc.
4. De-laminations and unevenness of surface.
5. Leakage, cracks in drainage system, dampness in sunk portions.
6. Defects in paint works, distempering, white-wash, etc. & unevenness in shade, pealing out, flakes on the surface, etc.
7. Cracks, settlement, unevenness, opening of joints in floorings.
8. Doors, Windows and Ventilators opening and closing are fitting & fixtures are not functioning smoothly.
9. Steel fabrication works not grinded properly and finished.
11. External services for storm water, sewerage, rain water harve not functioning properly.
additions to the above items the engineer-in-charge may add more in the nature of work which seems to be covered under 2 year guarantee from of commissioning.

GENERAL

1. Inspection of works during Defect Liability Period:
   The contracting agency shall undertake joint detailed inspection a Engineer-in-charge/ AEEn, at least once in three months in case Road/Bridge/C.D. works. The Engineer-in-charge can reduce this frequency in case of emergency. The Contraction agency shall forward to the Engineer-in-charge the record of inspection and rectification within 15 days after inspection. The Contracting agency shall pay particular attention on sections, which are likely to be damaged during rainy season.

   Once register has to be maintained by every AEEn for recording the details of works in his jurisdiction under defect liability period.

2. Conditions regarding Security Deposit

   * Security for DLP
      The contracting agency shall have to furnish security deposit in of Bank Guarantee for DLP as per requirements of clause Contract Agreement, valid from the date of completion, which is assigned by the Engineer-in-charge.

   Forfeiture of SD

      If case contraction agency fails to rectify the defects within period notified to him by the Engineer-in-charge concerned under agreement, the Engineer-in-charge shall serve a final notice for time from reckoned from the date of issue to rectify the defects. The contraction agency not responding to notice and fails in rectification of defects the Engineer-in-charge will get the defects removed and cost of the contracting agency. Action such as encashment Guarantee and action under enlistment rules etc. shall be taken by the competent authority.
In addition to the above, any defects identified by the user and/or Engineer-in-charge shall be rectified by the contracting agency within notified assigned by the Engineer-in-charge.

**Electrical Works:**

12. The defect liability under DLP for 2 years shall be from the completion of the works reckoned by the Engineer-in-charge.

13. The defect shall be in case of non-functioning of the following in Internal and External wiring, panels, cables, LT installation from distribution to end use points, MCBs/DBs, ELCBs, earthing, Switch distribution panels, panel switchgears, panel instruments, MCB cable trenching, Lugs, connecting wire and any other items specified in the contract.

14. Repair and Replacement – The items covered under defect liability shall be replaced and/or repaired as directed by the Engineer-in-charge.

15. Time period for repair/replacement – The Engineer in charge shall notify to the contracting agency and/or his representative on phone and in writing for rectification of the defect which may be in hours/days depending on the severity of defect.

16. Consumable Articles – Consumable Articles like tube rods, CF, fuses, Batteries, Gas filling will be replaced by the client department at their own cost and arrangement.

17. Other items:

1. D.G. Set including fitting and fixtures.
2. Lifts and Escalators.
3. Air cooling/Air conditioning/Heating System.
4. Fire fighting system.
5. CCTV, EPABX
The defect arises due to earthquake, cyclone, and natural calamities shall not be the responsibility of contraction agency.
The Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996, was enacted to regulate the conditions of service of the workers who are engaged in building and construction works and appropriate to their safety, health, and welfare. Under this Act of 1996, the Code provides for constitution welfare boards to implement welfare schemes for the workers on different subjects, like registration of employees (establishments and construction units), and the workers.

Your might be knowing that there is a need, which has been given special attention at Hon'ble Chief Minister, Chief Secretary, and Finance, etc. No need not to invest in it as the implementation of the Act is going to be discussed and reviewed at state level in the near future.

With a view of augmenting the resources of the welfare Board to under the Act of 1996, a separate corresponding Act, named "The Building and Other Construction Workers' Welfare Act, 1996," was also proposed to provide for the levy and collection of cess for the benefit of workers and employees. The Act itself will provide for the constitution of pensionary and abolition of pensionary for old employees.

Section 35(3) of Cess Act provides for levy of cess at the rate of 2% per unit of output. The cess rate vide its notification dated 13th April 1998 has been amended as per the Finance Act, 1998. The cess Act provides.

- Where the levy of cess per unit of output.
- Public Sector Unit (PSU), such cess, if the cess shall be reduced. The cess payable shall be paid by the
- Where the cess rate is constituted under.
by a I.D. for an amount of Case payable on the earlier completion.

(b) In other cases, an employer may pay amount of Case to the estimated cost of construction with the main commencement of work.

Thus, the collected Case shall be transferred by the G.O. by the local authorities or land collector to the District in prescribed manner with 30 days of its collection along with the challan.

I call your attention to inform you that a writ petition filed in a National campaign committee, C.L. Labour v. Union of India in court before the Hon'ble Supreme Court regarding non-implementation of the Act in the States and the State Govt. has to submit its affidavit before 1st of January in terms of implementation of said Act in the State.

Hence, you're requested to extend your full cooperation for frequent meetings of the concerned departments, PWD, local authorities and contractors related to building and other construction works of you to motivate and sensitize them regarding their responsibilities for real establishment and beneficiaries, deduction, collection and transfer of the land in revenue heads, so that the progress implementation of the scheme be carried out and the respective progress to the Hon'ble SC, is made accordingly. Your early and practical suggestions are welcomed.

With regards,

Sri Arul Sharma, IAS,
Director Commissioner,
Ahmedabad
CIRCULAR

Sub: Additional performance security on un-balanced bids.

A Bid is to be considered un-balanced if the bid price offered by the bidder is more than 10% lower than the cost worked out as per market rate analysis. For the purpose of determination of additional performance security, current BSR rates shall be considered as the market rates. If the BSR is not revised for the Current Financial Year, then only the market rate analysis is required and it should be uploaded on site before Bid receipt date in accordance with RTPP rules.

If "X" is the scheduled / market price of the work, then additional performance security shall be equal to:

0.9 X – Bid amount (Point nine multiplied by X minus Bid amount).

The additional performance security will be refundable after satisfactory completion of the work. This Order will be applicable from the date of issue both on Building as well as Road works under taken by the department. It bears approval of Govt. vide MR No.5000/M/PWD/2016 dated 19.09.2016.

(Sri Sathaur Sharma)
Chief Engineer & Addl. Secy., PWD, Rajasthan, Jaipur

Copy forwarded to the following for information and necessary action Please:
1. PS to Addl. Chief Secretary, PWD Rajasthan, Jaipur
2. PS to Secretary, PWD Rajasthan, Jaipur.
3. Chief Engineer PMSGY/NH/Bldg./QC/SS PWD Jaipur.
5. Superintending Engineer PWD Circle .......................... (All).
6. Executive Engineer PWD DIR .......................... (All).
7. LA-PS(K)/Bldg./SS/QC/SSNH/PMSGY, PWD C/O’s Office Jaipur.

(Sri Sathaur Sharma)
Chief Engineer & Addl. Secy., PWD, Rajasthan, Jaipur

Signature Not Verified
Digitally signed by LALIT KUNAR FAGARA
Date: 2017.05.03 16:00:55 IST
Location: Rajasthan